FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

facebook.com/fnind
twitter.com/fnind
focusnewsindia.blogspot.in

www.focusnews.co.in
+focusnewsin

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। शुक्रवार 16 जनवरी 2026। द्वादशी, माघ मास, कृष्ण पक्ष। 2081 विक्रम संवत। पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 13। अंक : 183

भारत में लोकतंत्र सफल है क्योंकि शासन के केंद्र में जनता है: पीएम मोदी

। कृष्णा अग्रवाल ।

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बनाया है और दुनिया को दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, गति तथा स्तर (स्केल) प्रदान करते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का उद्घाटन करते हुए, मोदी ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र सफल है क्योंकि शासन के केंद्र में देश की जनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक बड़े पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें गहरी हैं। मोदी ने कहा, ''भारत में, लोकतंत्र का मतलब है अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच।'' उन्होंने कहा कि जन कल्याण की भावना के साथ उठाए गए सरकार के कल्याणकारी कदम बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, ''इस भावना की वजह से 25 करोड़ लोग पिछले कुछ साल में गरीबी से बाहर आए हैं। भारत में लोकतंत्र सफल है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब भारत को आजादी मिली, तो कई लोगों को संदेह था कि देश की इतनी अधिक विविधता के बीच लोकतंत्र टिक पाएगा या नहीं। हालांकि, यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति बन गई।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''यह भी संशय था कि लोकतंत्र ने जड़ें जमा भी लीं, तो भी भारत को आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। (शेष पेज दो पर)

ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ: राजनाथ सिंह

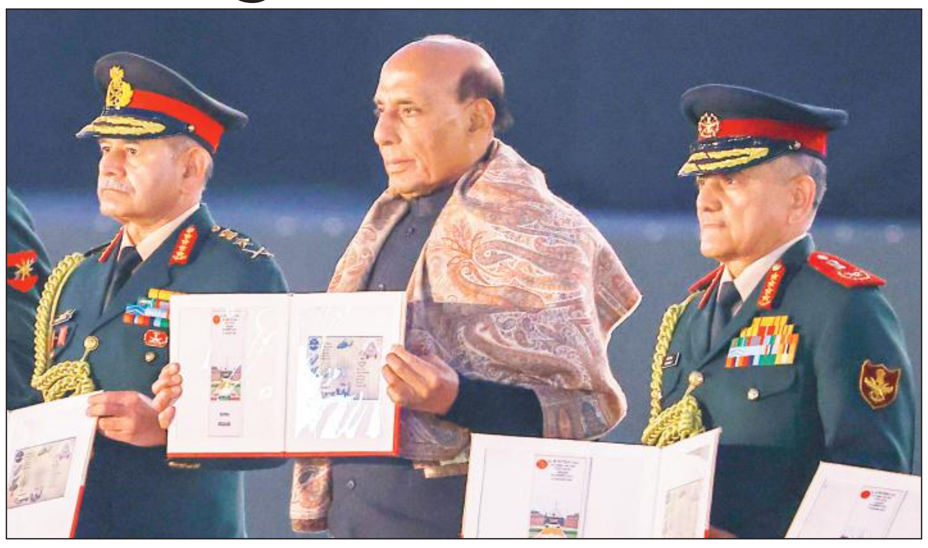

जयपुर, फोकस न्यूज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं का 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत के इतिहास में साहस व संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री, भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में यहां एसएमएस स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "यह भी सच है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से इसकी घोषणा कर रहा हूं।" रक्षा मंत्री ने कहा कि इस (ऑपरेशन सिंदूर) अभियान में भारत ने अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। उन्होंने कहा, "आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझ कर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत के इतिहास में सिर्फ सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि साहस व संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा।" सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देने के लिए सेना के जवानों को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवादी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीय सशस्त्र बल उनके खिलाफ इतनी बहादुरी और तेजी से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, ''हालात मुश्किल थे और दबाव भी था लेकिन हमारे (शेष पेज दो पर)

गंगा की स्वच्छता और जैवविविधता संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता: सी.आर. पाटिल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने गंगा नदी को भारत की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय और आर्थिक जीवन रेखा बताते हुए मंगलवार को कहा कि नदी की स्वच्छता और जैवविविधता का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

एमओसी से मंजूरी के बाद नीरज सत्र पूर्व ट्रेनिंग के लिए पोटचेफस्ट्रूम रवाना

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने अपने चुने हुए स्थल दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में सत्र पूर्व ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिये नया पोर्टल शुरू

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 'आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल' की शुरुआत की, जिसके जरिए देशभर के आयुर्वेद शिक्षण संस्थान मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रकृति विज्ञान के धरातल पर नवदुर्गाओं के दर्शन

देवी माहात्म्य अर्थात दुर्गा सप्शती का पाठ व श्रवण करने से सभी मनुष्यों पर मेरी कृपा दृष्टिबनी रहती है। दुःख, बाधाएं शांत हो जाती हैं और सुख–समृद्धि का एक नया वातावरण जन्म लेता है।

टॉक्सिक में धूम मचाएंगी तारा सुतारिया, ब्रेकअप की खबरों पर बटोरी सुर्खियां

तारा बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। शुक्रवार को तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया से ब्रेकअप की खबरें आती रहीं।

राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों को खारिज किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में मुख्यमंत्री पद पर संभावित बदलाव को लेकर मीडिया में जारी अटकलों को खारिज कर दिया।

चांदी 3,000 रुपये चढ़कर 2.89 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर, सोना ने भी बनाया रिकॉर्ड

चांदी की कीमत राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को 3,000 रुपये की तेजी के साथ 2,89,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

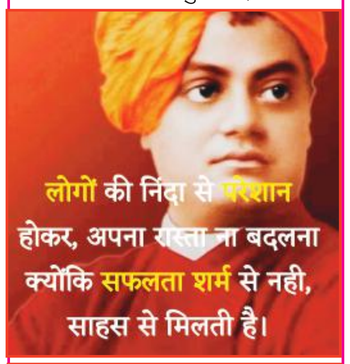

लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे, सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 32वीं किश्त, गैस सिलेंडर का पैसा भी मिलेगा

भोपाल। फोकस न्यूज। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बैंक खातों में शुक्रवार के दिन पैसे आने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार 16 जनवरी को राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में 'लाडली बहना' लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर (बाबई) में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक पात्र बहनों को 1,836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर गैस सिलेंडर (शेष पेज दो पर)

भारत की परंपरा ज्ञान की परंपरा है : दत्तात्रेय होसबाले

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारतमंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में 'मंत्र– विप्लव' पुस्तक का लोकार्पण किया। तरुण विजय द्वारा लिखित एवं प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के विमोचन समारोह में राज्यसभा सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी, पुस्तक के लेखक तरुण विजय तथा प्रभात प्रकाशन के चेयरमैन प्रभात कुमार भी उपस्थित थे। इस पुस्तक लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान की परंपरा है। इसी से यश, वैभव सभी की प्राप्ति हुई। अपने पूर्वजों को इस विषय पर स्पष्टता थी। उन्होंने कहा ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा में ले (शेष पेज दो पर)

वकीलों को न्याय प्रणाली के प्रशासनिक पक्ष में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए : प्रधान न्यायाधीश

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने वकीलों से न्याय प्रणाली के प्रशासनिक पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और कहा कि उन्हें केवल ''शिकायत दर्ज कराने'' से आगे बढ़ना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ''बार और बेंच'' प्रशासनिक नवाचार की जिम्मेदारी साझा करते हैं, तो संक्रमण काल के दौरान भी प्रणाली के अधिक विश्वासनीय बने रहे की संभावना होती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एक तैयार, नैतिक और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत बार न्याय प्रशासन को मजबूत करता है, और ऐसे (शेष पेज दो पर)

सेहत के लिए वरदान मशरूम, बूस्ट कर सकता है इम्यूनिटी, शरीर को मिलेंगे ढेर सारे फायदे

भारत में जहां कुछ लोगों को मशरूम खाना पसंद है तो वहीं कुछ लोग मशरूम का नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मशरूम में पाए जाने वाले तमाम पौष्टिक तत्व आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मशरूम खाने से सेहत को मिलने वाले कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में जानकर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे। हालांकि, फायदे हासिल करने के लिए मशरूम को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से बचना चाहिए।

मशरूम में पाए जाने वाले तमाम पोषक तत्व– प्लांट बेस्ट खाने की चीजों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और यही वजह है कि मशरूम खाने से आपकी सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। मशरूम में विटामिन्स, मिनरल्स, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत कई पौष्टिक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। बस सही मात्रा में और सही तरीके से मशरूम का सेवन करें।

सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे– अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आप बार–बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको (शेष पेज दो पर)

मकर संक्रांति पर करोड़ों भक्तों ने लगायी आस्था की डुबकी

प्रयागराज/वाराणसी/अयोध्या, (भाषा) मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न धार्मिक शहरों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में जारी माघ मेले में बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर शाम तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात 12 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था। पूरे दिन मकर संक्रांति का मुहूर्त रहने के कारण शाम तक करीब 1.03 करोड़ भक्तों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने बताया कि बुधवार को एकादशी के अवसर पर लगभग 85 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया था। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई 'बाइक टैक्सी' सेवा का भी व्यापक उपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को लगभग 11,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने 'बाइक टैक्सी' सेवा का लाभ लिया, जबकि अब तक माघ मेले में कुल 1,38,500 से अधिक लोग इस सेवा का उपयोग कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। वाराणसी में, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ बुधवार (शेष पेज दो पर)

बाल भी बांका नहीं कर पाएगी कड़कड़ाती ठंड, बस स्वेटर खरीदने से पहले रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

अगर आपने सर्दियों के मौसम में सही स्वेटर नहीं चुना, तो आप सर्दी के प्रकोप से खुद को बचा नहीं पाएंगे। सर्दियों में तबीयत को बिगड़ने से बचाएं और स्वेटर खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। आज हम आपको कुछ छोटी–छोटी टिप्स के बारे में बताएंगे और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप आसानी से सही स्वेटर का चुनाव कर (शेष पेज दो पर)

किस जगह को कहा जाता है भारत का 'कोकोनट आइलैंड', बेहद खूबसूरत है ये द्वीप, जरूर करें एक्सप्लोर

भारत में एक से बढ़कर एक घूमने की जगह हैं। अगर आपको घूमने–फिरने का शौक है, तो इस जगह पर जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ सुकून के पल जीने के लिए ये जगह एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। हम जिस बेहद खूबसूरत जगह की बात कर रहे हैं, वो है लक्षद्वीप। अगर आपने अभी तक इस आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आपको एक बार यहां पर जाने का प्लान जरूर बनाना चाहिए।

बेहद खूबसूरत द्वीप– क्या आप भी अक्सर घूमने के लिए पहाड़ों में जाने का प्लान (शेष पेज दो पर)

भारत में... (पेज एक का शेष) इन संशयों के उलट, भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, स्केल और गति प्रदान करते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है जहां यूपीआई के साथ सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली भी है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन विनिर्माता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात निर्माता भी है और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम है। मोदी ने कहा कि देश में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार, चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। यह सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश भी है। संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में 14 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे सीएसपीओसी में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। चौथी बार भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों की करीब 50 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जिसने सभी देशों के विकास में हरसंभव योगदान का प्रयास लगातार किया है।

उन्होंने कहा, ''भारत अपने साझेदार देशों से सीखने का सतत प्रयास करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत के अनुभवों का लाभ अन्य राष्ट्रमंडल देशों को भी मिले।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहस, संवाद और मिलकर फैसला लेने की लंबी परंपरा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर 'ग्लोबल साउथ' की चिंताओं को मजबूती से उठा रहा है। मोदी ने कहा, ''अपनी जी20 की अध्यक्षता के दौरान भी, भारत ने 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को वैश्विक एजेंडा के केंद्र में रखा था।'' इसमें आज के कई संसदीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाकर रखने में अध्यक्ष (स्पीकर) और पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी शामिल है। संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल, संसद सदस्यों पर सोशल मीडिया का असर, संसद के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीति और मतदान के अलावा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने आदि पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर... (पेज एक का शेष) सैनिकों ने जिस संयम, एकता और धैर्य के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया वह अभूतपूर्व और तारीफ के काबिल है।'' सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं होता बल्कि एक दार्शनिक व कुशल प्रबंधक होता है क्योंकि सैनिक का जीवन 'सेवा परमो धर्म' पर आधारित है। उन्होंने कहा, ''भारतीय सेना अपने आप में देश के लिए, नागरिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कई मायनों में विशाल है। कोई भी जब भारतीय सेना को देखता है तो हमें पूरा भारत दिखाई देता है। भारतीय सेना अपने आप में विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है।'' रक्षा मंत्री ने कहा, ''सेना ने भारत की सामाजिक एकता को मजबूत करने में अतुल्य योगदान दिया है। यही कारण है कि भारतीय सेना एक सैन्य बल नहीं है यह राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तम्भ है।'' सिंह ने कहा, ''दूसरे देशों में आम तौर पर सेना का नागरिकों के साथ बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है जबकि भारत में सेना नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है। जनता, सेना पर अटूट विश्वास करती है। मैं मानता हूं कि यह विश्वास ही सेना की सबसे बड़ी ताकत है।'' उन्होंने कहा कि जनता व सेना के बीच पारस्परिक विश्वास का बंधन ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे की नींव है। सिंह ने सुधारों के लिए भारतीय सेना द्वारा उठाये गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दिखाया कि संगठन बड़ा होने के बावजूद भी अगर इच्छा शक्ति है तो सुधारों को तेजी से लागू करने में कोई समस्या नहीं आती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सशक्त सेना बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहा स्थापित धारणाएं टूट रही हैं या तोड़ी जा रही हैं। दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि सेनाओं का मजबूत रहना और सेनाओं का आधुनिक और आत्मनिर्भर रहना किसी भी देश के अस्तित्व के लिए आज जितना महत्वपूर्ण हो चुका है उतना पहले कभी नहीं रहा।'' उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में सेनाओं का मजबूत रहना सर्वोपरि है। हमारी सेनाएं हमारी प्राथमिक ताकत है।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल ने इस बात पर बल दिया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ गर्व की बात नहीं बल्कि जरूरत है। उन्होंने कहा, ''देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर काफी आगे बढ़ गया है, जिसमें सशस्त्र बलों ने आगे बढ़कर इस कोशिश में अहम योगदान दिया है।'' सिंह ने आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इन कोशिशों को और तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध के आयामों के विस्तार को देखते हुए 'इंटर–सर्विस लिंकेज' को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सशस्त्र बलों को भारत की जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों और मंच से लैस कर रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपये था जो बढ़कर रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात 2014 में 1,000 करोड़ रुपये से कम था जो बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 24,000 करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारतीय सैनिकों के योगदान पर भी प्रकाश डाला। सिंह ने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर, उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं को सशस्त्र बलों में सहायक भूमिकाओं में भर्ती किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी भूमिका का विस्तार करने की कल्पना की।

मकर संक्रांति... (पेज एक का शेष) रात से ही घाटों पर उमड़ने लगी थी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मकर संक्रांति के अवसर पर बृहस्पतिवार को बाबा विश्वनाथ धाम में विशेष मध्याह्न भोग आरती का आयोजन किया गया। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाबा को मध्याह्न भोग में खिचड़ी, चिवड़ा, मूंगफली की पट्टी और पापड़ अर्पित किए गए। भोग अर्पण के बाद मंत्रोच्चार के बीच आरती की गई।

किस जगह... (पेज एक का शेष) बना लेते हैं? अगर हां, तो कई पहाड़ों में आपको खूबसूरत वादियों से ज्यादा भीड़भाड़ देखने को मिलेगा। इस बार क्यों न कुछ अलग किया जाए? आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बना सकते हैं। लक्षद्वीप को परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ या फिर सोलो ट्रिप पर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। **द कोकोनट आइलैंड**– लक्षद्वीप को नारियल द्वीप/द कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों? दरअसल, यहां के द्वीपों में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। नारियल यहां के स्थानीय भोजन के साथ–साथ आजीविका, पारंपरिक रीति–रिवाजों और लघु उद्योगों के लिए भी जरूरी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप का नाम कब और कैसे पड़ा था? लक्षद्वीप को पहले लक्कादीव–मिनिकॉय–अमिनीदिवि के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसके नाम को बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप का मतलब एक लाख द्वीप है। **एक्सप्लोर करने लायक जगह**– लक्षद्वीप में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं। आप मिनीकॉय, अगाती, बंगारम, कदमत और कवरत्ती जैसे खूबसूरत आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां के शांत समुद्र तट और साफ पानी टूरिस्ट्स को काफी आकर्षित करते है। अगर आप एडवेंचरस हैं, तो आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग और लाइटहाउस जैसी एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं।

भारत की... (पेज एक का शेष) जाता है। ज्ञान के साथ भक्ति की भी आवश्यकता होती है क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान से अहंकार आ जाता है। उन्होंने बताया कि महर्षि अरविन्दो ने स्वतंत्र भारत में तीन कार्य करने की आवश्यकता बताई थी। पहला, अपने देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा जो विखरे पड़े है उसको इकत्र करना चाहिए। दूसरा, उसको आज के समय के अनुरूप जीवन उपयोगी तथा मानव उपयोगी बनाना होगा। तथा तीसरा, नए ज्ञान सृजन भी करना है। सरकार्यवाह ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के शब्दों के बारे में अभी बहुत अध्ययन होना बाकी है। गलत विमर्श गढ़ने के हो रहे प्रयास पर उन्होंने कहा कि सत्य और इतिहास को विकृत करते हुए प्रस्तुत करने का कुलषित प्रयास हुआ है। यह सब अज्ञान के कारण नहीं अपितु अजेन्डा से हुआ है। समाज में संभ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ। जैसे–जैसे दूसरों का हमारे मन दृ बुद्धि पर नियंत्रण होता गया, मंत्र–विप्लव की स्थिति पैदा होती गई। सरकार्यवाह जी ने बताया कि सम्मोह से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि के नाश से सर्वनाश होता है।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारे समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा एम फैक्टर (मैकाले, मुगल एवं मार्क्स) से एडिक्ट हो गया है। समाज के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियाँ है दृ एक जो दिखाई देता है तथा दूसरा जो संक्रमण की तरह दिखाई नहीं देता है। मंत्र दृ विप्लव इन नहीं दिखाई देने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है तथा उनसे निपटने का मार्ग भी दिखाता है। पुस्तक के लेखक तरुण विजय ने मंत्र दृ विप्लव पुस्तक के विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था – 'विष की एक बूँद जिसे दी जाए, उससे केवल वही एक व्यक्ति मरता है। विषैला तीर जिस व्यक्ति पर आघात करे, उससे भी केवल वही एक व्यक्ति मारा जाता है, पर अगर विचार ही भ्रष्ट हो जाए और उसकी समझ में राजा और प्रजा में संभ्रम निर्माण हो तो हे धृतराष्ट्र, उस समय मंत्र–विप्लव की स्थिति पैदा होती है, जिसमें राजा, प्रजा और राष्ट्र–तीनों का नाश हो जाता है।' इस पुस्तक के लेखों में उसी मंत्र–विप्लव की स्थिति का प्रतिकार है। उस स्थिति को रोकने टालने का जतन है।

लाडली बहनों... (पेज एक का शेष) रिफिलिंग सहायता के लिए 29 लाख लाभार्थियों के खातों में 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूमि पूजन भी करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार का संकल्प है। कल मैं 'लाडली बहना' योजना की लाभार्थियों के बैंक खातों में 32वीं किस्त ट्रांसफर करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा।"

2023 में शुरू हुई थी योजना : लाडली बहना योजना ' जून 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपये की वृद्धि की गई। इसके साथ ही, पात्र महिला लाभार्थियों को अब प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है। जून 2023 से अब तक, दिसंबर 2025 तक मासिक वित्तीय सहायता की 31 किस्तें लाभार्थियों के खातों में नियमित रूप से ट्रांसफर की जा चुकी हैं। 32वीं किस्त जनवरी 2026 में हस्तांतरित की जाएगी।

अब तक कितना बजट खर्च हुआ: जून 2023 से दिसंबर 2025 तक, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 48,632.70 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। अकेले जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच 38,635.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ' ने राज्य भर की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित किया है। आने वाले समय में, लाभार्थी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त हो सकेंगी।

बाल भी... (पेज एक का शेष) पाएंगे। जब भी स्वेटर खरीदने जाएं, तो इस आर्टिकल में बताई गई बातों को अपने दिमाग में जरूर रखें।

चेक करें स्वेटर का फैब्रिक– सर्दियों में खुद को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर खरीदते समय सबसे पहले उसके फैब्रिक पर ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊन, मेरिनो वूल, कश्मीरी या फिर वूल ब्लेंड से बने स्वेटर अच्छे और ज्यादा गर्म होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मटीरियल से बने स्वेटर हल्के होते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है।

फिटिंग पर ध्यान दें– स्वेटर खरीदने से पहले एक बार स्वेटर को पहनकर जरूर देखिए। आपको बता दें कि स्वेटर की अच्छी फिटिंग ठंड से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। जहां ज्यादा टाइट फिटिंग वाले स्वेटर से हवा अंदर जा सकती है, तो वहीं ज्यादा ढीले स्वेटर से गर्मी नहीं रुक पाती है। सही फिटिंग वाले स्वेटर खरीदें जिससे आप ठंड के प्रकोप से बच पाएं।

स्वेटर की बुनाई कैसी है– आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ढीली बुनाई वाले स्वेटर से हवा अंदर पहुंच सकती है। यही वजह है कि आपको मोटी और घनी बुनाई वाले स्वेटर को खरीदना चाहिए। स्वेटर खरीदते समय आप अपने हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं कि हवा स्वेटर से पास तो नहीं हो रही है।

ऊन कितना प्रतिशत– सिर्फ स्वेटर का डिजाइन देखकर स्वेटर खरीदने का फैसला न लें। टैग पर लिखी हुई एक जरूरी जानकारी पढ़ना न भूलें। दरअसल, टैग पर लिखा होता है कि स्वेटर में कितने प्रतिशत ऊन का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा–सीधा मतलब ये है कि ज्यादा ऊन वाला स्वेटर ठंड में ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप चाहें, तो वूल ब्लेंड वाले स्वेटर खरीद सकते हैं।

सेहत के... (पेज एक का शेष) मशरूम का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। मशरूम आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में पाए जाने वाले तत्व आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं मशरूम में पाए जाने वाले तत्व आपकी बोन हेल्थ को भी काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं।

मोटापे से पाएं छुटकारा– पोशक तत्वों से भरपूर मशरूम आपकी वेट लॉस जर्नी को भी आसान बना सकते हैं। अगर आप मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मशरूम को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। मशरूम को न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। मशरूम आपके ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने में भी कारगर साबित हो सकता है।

वकीलों को... (पेज एक का शेष) बार को प्रोत्साहित करके और उसकी ताकत को स्वीकार करके, व्यवस्था की नींव को मजबूत किया जाता है। उन्होंने कहा, ''बार को केवल शिकायतें दर्ज कराने तक सीमित न रहकर सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मैं बार के सदस्यों से न्याय प्रशासन में पूरी तरह से शामिल होने का आह्वान करता हूं, ताकि वे व्यावहारिक सुझाव दें, नयी प्रणालियों को आगे बढ़ाएं और परामर्श प्रक्रियाओं में भाग लें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सुधार न केवल नेक इरादे से किए गए हों, बल्कि व्यावहारिक भी हों।'' डीएचसीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कुछ ''गंभीर संस्थागत चिंताओं'' को रेखांकित किया, जैसे कि अपर्याप्त आधारभूत ढांचा और उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के रूप में वकीलों की ''पदोन्नति के अवसर में कमी''। हरिहरन ने कहा, ''47,000 अधिवक्ताओं के बावजूद, अगस्त 2024 से अब तक केवल तीन को ही न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है।'' उन्होंने कहा कि वे उच्च न्यायालय में की गई किसी भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हरिहरन ने उच्च न्यायालय में रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया।

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

दिल्ली कैबिनेट ने 'कार्बन क्रेडिट' नीति को दी मंजूरी, जानिए इस फैसले से क्या लाभ होगा?

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार को हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में पर्यावरण विभाग की ओर से लाए गए 'कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क' लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दिल्ली सरकार अब अपने विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट्स से होने वाली उत्सर्जन कटौती को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर राजस्व जुटाएगी। इस 'कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क' के लागू होने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्राप्त होंगे, जिसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की इस योजना से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को विकास कार्यों में लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के मुताबिक यह योजना सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही पहल को कवर करेगी। पर्यावरण विभाग इस पूरे काम का नोडल विभाग होगा। दिल्ली सरकार वर्तमान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने, बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और कचरा प्रबंधन जैसे कई ऐसे काम कर रही है जिनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। इस नई नीति के तहत, इन सभी कामों से होने वाली प्रदूषण की कमी को वैज्ञानिक तरीके से मापा जाएगा और उन्हें 'कार्बन क्रेडिट' के रूप में रजिस्टर कराया जाएगा। इन क्रेडिट्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट में बेचा जा सकेगा, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका वित्तीय मॉडल है। दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के जरिए एक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन करेगा। यह एजेंसी देखेगी कि किन–किन योजनाओं से कार्बन क्रेडिट बन सकते हैं। इसके बाद उनका डाक्यूमेंटेशन और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर रजिस्ट्रेशन का सारा काम भी करेगी। यह पूरी प्रक्रिया 'रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल' पर आधारित होगी यानी सरकार को इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। इससे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में आएगा।

न्यायालय ने आरटीई के तहत आरक्षित सीटों के प्रावधान लागू करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया कि निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश में 25 प्रतिशत कोटा लागू हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना ''एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देना उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकार का दायित्व है। न्यायालय ने कहा कि इसी तरह, अदालतों को, चाहे वे संवैधानिक हों या दीवानी, उन अभिभावकों को सुगम पहुंच और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए जो इस अधिकार से वंचित होने की शिकायत करते हैं। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से संबंधित पहलुओं पर विचार कर रही है, जिसमें निजी गैर–सहायता प्राप्त गैर–अल्पसंख्यक स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है। पीठ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिनके बच्चों को 2016 में पड़ोस के एक स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं मिला था, जबकि सीटें उपलब्ध थीं। इसके बाद, उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने आरक्षित सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन न करने के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि ''दुर्भाग्यवश'', उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध याचिका लंबे समय से लंबित थी। शीर्ष अदालत ने कहा, ''हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता जैसे अभिभावकों को इस तरह की स्थिति का बार–बार सामना न करना पड़े, हमने इस मामले को एक मिसाल कायम करने के लिए उचित समझा और आरटीई अधिनियम की धारा 12 (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की जिम्मेदारी का दायरा) के प्रावधान का अनुपालन करने की प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करने का निर्णय लिया।''

गोवा कार्निवल उत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा

पणजी, (भाषा) गोवा कार्निवल 14 फरवरी से शुरू होगा। यह कार्निवल तटीय राज्य के सबसे जीवंत सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है और रंगारंग जुलूसों और झांकी परेडों के लिए लोकप्रिय है। परंपरागत रूप से इसकी अगुवाई राजा मोमो करते हैं। अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह कार्निवल गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्सव की भावना का प्रतीक है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उत्सव का आरंभ 13 फरवरी को पणजी के पास पोरवोरिम में पारंपरिक उद्घाटन समारोह के साथ होगा। लैटिन अमेरिका के कई उत्सवों में किंग मोमो को कार्निवल का राजा माना जाता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे और अन्य लोग 14 फरवरी को पणजी में औपचारिक कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद उत्सव पणजी में आयोजित किया जाएगा, जहां न्यू पट्टो ब्रिज से कैम्पल ग्राउंड तक के मार्ग पर कार्निवल परेड का आयोजन किया जाएगा। ये परेड क्रमशः 15 और 16 फरवरी को दक्षिण गोवा के मारगाओ और वास्को शहर में आयोजित की जाएंगी।

पीजीडीएवी सांध्य कॉलेज में लगीः स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर पुस्तक प्रदर्शनी

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 'पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य)' के पुस्तकालय द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन व दर्शन पर आधारित पुस्तकों की एक पुस्तक प्रदर्शनी लगायी गयी। पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए 'कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर रवींद्र कुमार गुप्ता' ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सवामी विवेकानंद जी के विचार, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणादायक हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना से जीवन जिएं, हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सब के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है व प्रेरक है। पुस्तक प्रदर्शनी में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से संबंधित 200 से अधिक पुसकों को प्रदर्शित किया गया था। पुस्तक प्रदर्शनी में कालेज के विद्यार्थी, संकाय सदस्यों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. निखिल यादव–लेखक एवं सह प्रमुख विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह –अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल, दिल्ली प्रांत, पुस्तकालयाध्यक्ष पवन कुमार मैठानी, पुस्तकालय कमेटी के फैकल्टी सदस्य , व अन्य फकल्टी सदस्य उपस्थित रहे। युवा दिवस पर कालेज में 'विकसित भारत स्व का बोधः उठो और जागो, स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण' बिषय पर व्याख्यान व विद्यार्थियों के लिए लेख व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जनवरी को 10,000 कलाकारों के बागुरुम्बा नृत्य का अवलोकन करेंगे

गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जनवरी को यहां अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10,000 कलाकारों द्वारा पेश किए जाने वाले बोडो लोक नृत्य 'बागुरुम्बा' का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री 17 जनवरी को असम के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''17 जनवरी को अब तक के सबसे भव्य बागुरुम्बा प्रदर्शन के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है।'' उन्होंने लिखा कहा, '' नरेन्द्र मोदी जी इस शानदार प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे और 10,000 से अधिक कलाकारों के साथ भोगली भावना का आनंद लेंगे।'' मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में कलाकारों के अभ्यास का एक वीडियो भी 'एक्स' पोस्ट किया। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को 6,957 करोड़ रुपये के 'काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर' की आधारशिला रखने के लिए कलियाबोर का दौरा करेंगे। मोदी का दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन – डिब्रूगढ़–गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या–रोहतक – को डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाने और कलियाबोर में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।

देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे अल्पसंख्यक समाजः रीजीजू

लखनऊ, (भाषा) केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने अल्पसंख्यक समाज से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके बिना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। रीजीजू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा यहां आयोजित 'अल्पसंख्यक स्नेह संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी समाज, जाति या वर्ग के साथ भेदभाव किए बिना सर्व समाज के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को अलग–थलग रखकर विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मैं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आप सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि हूं। इसलिए मैं आप सभी से विशेष रूप से यह आग्रह करने आया हूं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करें।'' उन्होंने कहा, ''आप लोगों की भागीदारी के बिना विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।'' रीजीजू ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज यदि संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करें तो भारत को सशक्त व विकसित बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संवाद कार्यक्रम में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समाज के धर्मगुरुओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

गंगा की स्वच्छता और जैवविविधता संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकताः सी.आर. पाटिल

देहरादून, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने गंगा नदी को भारत की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय और आर्थिक जीवन रेखा बताते हुए मंगलवार को कहा कि नदी की स्वच्छता और जैवविविधता का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यहां भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) में आयोजित एक कार्यक्रम में पाटिल ने कहा कि संस्थान परिसर में राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया है, जो भारत में नदी संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और जैवविविधता संवर्धन के राष्ट्रीय प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने संस्थान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व के लिए बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यहां से शुरू हुए ये अभिनव प्रयास नयी ऊंचाइयों को छुएंगे और सिमटती जैवविविधता के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। जलीय जैवविविधता संरक्षण एवं अनुश्रवण केंद्र के नाम से भी पहचाने जाने वाला राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केंद्र भारत में नदियों और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को सुदृढ़ करने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गंगा में जलीय जीवों के संरक्षण और आपातकालीन बचाव कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए एक 'डॉल्फिन रेस्क्यू वैन' को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

छात्र केवल रोमांचक क्षणों का ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के कामों का भी आनंद लें : ग्रुप कैप्टन शुक्ला

नयी दिल्ली, (भाषा) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) जाने वाले पहले भारतीय, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में मंगलवार को छात्र–छात्राओं के साथ अपने बचपन से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि छात्रों को केवल रोमांचक क्षणों का ही नहीं, बल्कि साधारण और रोज़मर्रा के कामों का भी आनंद लेना चाहिए। शुक्ला ने अपने डर को भी खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने बताया, ''जब फाल्कन–9 रॉकेट के इंजन स्टार्ट हुए तो मेरे शरीर की हर हड्डी कॉंप रही थी। ऐसा लग रहा था, जैसे सारी तैयारी करने के बावजूद प्रश्नपत्र सामने आते ही आप सब कुछ भूल गया हो।'' उन्होंने फेफड़ों पर दबाव, साँस लेने में कठिनाई जैसी शारीरिक परेशानियों के साथ परिवार से दूर रहने की मानसिक चुनौती के बारे में भी ईमानदारी से बताया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एनबीटी–इंडिया के निदेशक युवराज मलिक द्वारा यहां नयी दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में संचालित एक सत्र में ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने युवा दर्शकों को भारतीय वायु सेना के पायलट के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर जाने तक की प्रेरक यात्रा सुनाई। उन्होंने विद्यार्थियों के उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उनमें से कोई भविष्य का अंतरिक्ष यात्री बनकर भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में केवल 20 दिन बिताने के लिए उन्हें पाँच वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ा। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि उन्हें केवल रोमांचक क्षणों की ही नहीं, बल्कि साधारण और रोज़मर्रा के कामों की भी आनंद लेना सीखना चाहिए। शुक्ला ने बताया कि उन्हें जितनी तैयारी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए करनी पड़ी थी, वैसा ही अभ्यास धरती पर लौटने के बाद करना पड़ा। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल को फिर से महसूस करना, यहाँ तक कि अपनी पलकों का वजन भी महसूस होता था और लौटकर वापस सीधी रेखा में चलने का अभ्यास, ऐसे ही कौशल थे, जिन्हें उन्हें फिर से सीखना पड़ा। उन्होंने छात्रों को मोबाइल फोन का बेहतर उपयोग करने, पढ़ने, सीखने और पॉडकास्ट सुनने की सलाह दी और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुस्तक 'विंग्स ऑफ फायर' पढ़ने की सिफारिश की। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि डर केवल भविष्य की चिंता है। उन्होंने अपने मार्गदर्शकों और प्रेरणास्रोतों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को याद करते हुए कहा कि चार दशक बाद भी अंतरिक्ष से भारत को लेकर शर्मा का ऐतिहासिक कथन ''सारे जहाँ से अच्छा'' ही सबसे बेहतर है। आज राकेश शर्मा का जन्मदिन है। शुक्ला ने अपनी कमांडर डॉ. पैगी व्हिटसन का भी उल्लेख किया और बताया कि अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्हें नौ बार ठुकरा दिया गया था, जबकि आज वह विश्व की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। शुक्ला ने बच्चों से कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल संस्थानों के भरोसे नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों से आगे बढ़ेगी, जो सुविधा के बजाय साहस, डर के बजाय जिज्ञासा को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहां बैठा कोई बच्चा एक दिन भारत का तिरंगा पृथ्वी से परे लेकर जाए।

लोकतंत्र के लिए फेक न्यूज– मौन लेकिन गहरा खतरा

लोकतंत्र की सफलता का आधार एक जागरूक, सूचित और विवेकशील नागरिक समाज होता है। जब नागरिक सही और तथ्यपरक जानकारी के आधार पर अपने विचार तथा निर्णय बनाते हैं, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है किंतु वर्तमान डिजिटल युग में फेक न्यूज यानी झूठी और भ्रामक खबरें लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तीव्रता ने असत्य को इस कदर फैलाया है कि कई बार सत्य उसकी चपेट में आ जाता है। फेक न्यूज केवल गलत सूचना भर नहीं होती बल्कि यह सुनियोजित ढंग से तैयार की गई ऐसी सामग्री भी हो सकती है जिसका उद्देश्य जनमत को प्रभावित करना, राजनीतिक लाभ लेना, सामाजिक विद्वेष फैलाना या आर्थिक फायदा उठाना होता है। आधी–अधूरी सूचनाएं, संदर्भ से काटे गए बयान, एडिट किए गए वीडियो और सनसनीखेज शीर्षक इसके सामान्य रूप हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब लोग बिना सत्यापन के ऐसी खबरों को आगे साझा कर देते हैं। लोकतंत्र पर फेक न्यूज का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जनमत पर पड़ता है। चुनावी समय में फैलने वाली अफवाहें और झूठे प्रचार मतदाताओं की सोच को भ्रमित कर देते हैं। नागरिक सही मुद्दों के बजाय भावनात्मक और भ्रामक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसके अलावा, लगातार झूठी खबरों के कारण मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासन और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर होने लगता है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। फेक न्यूज सामाजिक ताने–बाने को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं समाज में अविश्वास, तनाव और नफरत को जन्म देती हैं। कई बार यह स्थिति हिंसा तक पहुंच जाती है जिससे सामाजिक सौहार्द और शांति भंग होती है। इस प्रकार फेक न्यूज न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है बल्कि सामाजिक एकता को भी खतरे में डाल देती है। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम सनसनीखेज और उत्तेजक सामग्री को तेजी से फैलाते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण लोग खबरों के स्रोत और सत्यता की जांच नहीं कर पाते। राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैचारिक कट्टरता भी झूठी खबरों के प्रसार को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही, क्लिकबेट संस्कृति और विज्ञापन आधारित कमाई ने फेक न्यूज को एक लाभकारी उद्योग का रूप दे दिया है।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसकी जिम्मेदारी सत्य को सामने लाने की होती है हालांकि प्रतिस्पर्धा और टीआरपी की दौड़ में कई बार मीडिया भी तथ्यों की अनदेखी कर देता है जिससे समस्या और गहराती है। ऐसे में मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी और आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है। डिजिटल साक्षरता को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा, ताकि नागरिक खबरों का विवेकपूर्ण विश्लेषण कर सकें। स्वतंत्र फैक्ट–चेकिंग संस्थाओं को प्रोत्साहन देना और उनकी पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही, संतुलित और स्पष्ट कानूनों के माध्यम से फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करना और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी समय की मांग है। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए एक मौन लेकिन गहरा खतरा है। इससे निपटने के लिए केवल कानून या तकनीक ही नहीं बल्कि नागरिकों की जागरूकता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता भी आवश्यक है। जब समाज सत्य को प्राथमिकता देगा और जिम्मेदारी से सूचना का उपयोग करेगा, तभी लोकतंत्र इस संकट से सुरक्षित रह सकेगा।

डा वीरेन्द्र भाटी मंगल

भाजपा 'वीबी-जी राम जी' में निहित प्रतिबद्धता को लेकर गांव, चौपालों पर पहुंचकर जनसंवाद करेगी

लखनऊ, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 'विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन–ग्रामीण' (वीबी–जी राम जी) में निहित गांव, गरीब और किसान के सर्वांगीण विकास, आर्थिक उन्नति और समृद्धि की प्रतिबद्धता को लेकर गांव, गली और चौपालों पर जाकर जनसंवाद करेगी। पार्टी के एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी। भाजपा के राज्य मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया कि यह निर्णय मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की कार्यशाला में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रीजीजू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'वीबी–जी राम जी' अधिनियम 2025 के तहत गांव के विकास और गरीब की आर्थिक उन्नति पर संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री सुरेन्द्र नागर, प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह तथा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। बयान के अनुसार बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि 'वीबी–जी राम जी' विकसित भारत की मजबूत नींव साबित होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 'वीबी–जी राम जी' से भ्रष्टाचार खत्म होगा, गांव का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नयी अवसंरचनाएं खड़ी होंगी। चौधरी ने कहा कि 'वीबी–जी राम जी' के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिन का रोजगार गारंटी के तौर पर मिलेगा, जबकि वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश कार्यशालाओं के बाद जिला कार्यशालाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर सम्मेलन, श्रमिक चौपाल और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। हर गांव में चौपालों के माध्यम से किसान, कृषि श्रमिक और श्रमिकों से सीधे संवाद कर वीबी–जी राम जी से होने वाले लाभ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, घर–घर संपर्क, किसान पद यात्रा, ट्रैक्टर रैली और बैलगाड़ी रैली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी जनसंवाद किया जाएगा।

आईएसएल को एएफसी से मान्यता मिली: एआईएफएफ

नयी दिल्ली, (भाषा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि फुटबॉल की महाद्वीपीय संस्था एएफसी (एशियाई फुटबॉल परिसंघ) ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) को छोटे हुए 2025–26 सत्र को मान्यता दे दी है और देश के शीर्ष दो डिविजन विजेताओं को क्षेत्रीय क्वालीफायर के माध्यम से एशियन चैंपियंस लीग 2 के लिए अप्रत्यक्ष स्थान दिए जाएंगे। सत्र की देरी से शुरुआत के कारण क्लब एएफसी चैंपियंस लीग 2 में खेलने के लिए योग्य होने के लिए अनिवार्य 24 मैच नहीं खेल पाएंगे जिसमें शीर्ष डिविजन लीग और घरेलू कप शामिल हैं। ज्यादातर क्लबों के सत्र के दौरान कुल 16 मैच खेलने की उम्मीद है जिसमें एआईएफएफ सुपर कप में कम से कम तीन मैच और आईएसएल में 13 मैच शामिल हैं। एएफसी ने 15 जनवरी को एआईएफएफ को लिखे एक पत्र में कहा, ''अनुच्छेद 3.4 और 3.5 के अनुसार किसी सदस्य संघ को दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थान को छोड़कर, अगर कोई सदस्य संघ पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है तो वह केवल संबंधित एएफसी क्लब प्रतियोगिता के लिए केवल अप्रत्यक्ष (मतलब सीधे नहीं बल्कि क्वालीफाइंग के जरिए) स्थान ही प्राप्त करने योग्य होगा, बशर्ते कि अनुच्छेद 4.4 के नियम लागू हों। '' एएफसी के प्रतियोगिता और फुटबॉल उप महासचिव शिन मान गिल ने कहा, ''ऐसे मामलों में संबंधित एएफसी क्लब प्रतियोगिता में संबंधित सदस्य संघ के लिए सीधे स्थान की संख्या पूरी तरह से अप्रत्यक्ष स्थान में बदल दी जाएगी। '' आईएसएल का 2025–26 सत्र 14 फरवरी से शुरू होने वाला है जिसमें सभी 14 टीम ने मंगलवार को अपनी भागीदारी की पुष्टि की जिससे संक्षिप्त हुए सत्र में 91 मैच खेले जाएंगे जिसमें हर टीम एक–दूसरे के खिलाफ एक चरण के मैच (13) खेलेगी। एएफसी के पत्र के अनुसार, ''इसे देखते हुए सूचित किया जाए कि अगर 2025–26 आईएसएल सत्र आपके पत्र में प्रस्तावित तरीके से आयोजित किया जाता है तो संबंधित एएफसी क्लब प्रतियोगिताओं में प्रवेश के उद्देश्यों के लिए प्रवेश नियम अनुच्छेद 4.3 के अनुसार ही लागू होंगे। '' इससे पहले आईएसएल क्लबों ने एआईएफएफ से एएफसी से 24 मैच की न्यूनतम अनिवार्यता में एक बार छूट देने का अनुरोध किया था ताकि वे एसीएल 2 में खेल सकें। क्लब के प्रस्ताव को मानते हुए एआईएफएफ के उप महासचिव एम सत्यनारायण ने एएफसी को पत्र लिखकर इस सत्र के लिए एक बार की छूट मांगी थी।

इंडिया ओपन: लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में जबकि सात्विक–चिराग, श्रीकांत, प्रणय बाहर

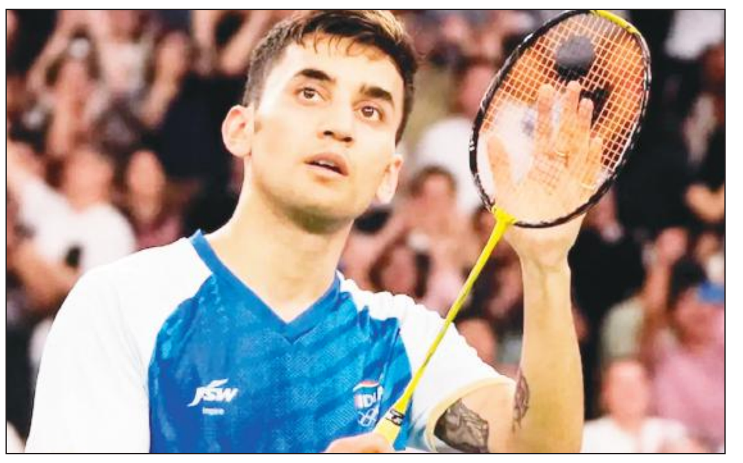

नयी दिल्ली, (भाषा) पूर्व चैंपियन लक्ष्य सेन ने संयमित और रणनीतिक प्रदर्शन से बृहस्पतिवार को यहां 950,000 डॉलर राशि के इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई जबकि किदांबी श्रीकांत और एच एस प्रणय चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन के बाद बाहर हो गए। प्रबल दावेदारों में शुमार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी भी दूसरे दौर में जापान के हिरोकी मिडोरिकावा और क्योहेई यामाशिता से 27–25 21–23 19–21 से हार के बाद बाहर हो गई। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सेन ने लचीलापन और परिपक्वता दिखाते हुए दूसरे दौर में जापान के केंटा निशिमोटो को 21–19, 21–11 से हराया और एकल वर्ग में एकमात्र भारतीय चुनौती के रूप में उभरे। लक्ष्य ने पत्रकारों से कहा, ''पहले गेम की शुरुआत में मैं अपनी लय से थोड़ा जूझ रहा था जिससे उसे ज्यादा आक्रमण करने का मौका मिल रहा था। लेकिन फिर मैंने शटल को लंबा लिफ्ट करना शुरू किया और अच्छी तरह से बचाव करने पर ध्यान केंद्रित किया और मुझे लगता है कि इससे पहला गेम पलट गया। '' उन्होंने कहा, ''दूसरे गेम में मुझे पता था कि मैं उसे अपना गेम खेलने का मौका नहीं दे सकता इसलिए मैंने अपनी स्पीड में बदलाव किया और यह काम कर गया। '' अल्मोड़ा के 24 वर्षीय खिलाड़ी का सामना अब चीनी ताइपे के लिन चुन–यी से होगा जिन्होंने आयरलैंड के न्हाट गुयेन को 21–16, 21–17 से हराया। इससे पहले श्रीकांत ने कड़ी टक्कर दी लेकिन फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से 21–14, 17–21, 21–17 से हार गए। प्रणय भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर देने के बाद सिंगापुर के आठवें वरीय लोह कीन यू से 18–21, 21–19, 21–14 से हार गए। मालविका बंसोड़ भी महिला एकल मैच में चीन की पांचवीं वरीय हान यू से 18–21 15–21 से हार गईं। महिला युगल में भी भारत की चुनौती खत्म हो गई जिसमें त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद 84 मिनट तक चले मैराथन मैच में चीन की सातवीं वरीयता प्राप्त ली यिजिंग और लुओ जुमिन की जोड़ी से 22–20 22–24 21–23 से हार गईं। सेन को शुरुआत में दिक्कत हुई जिससे निशिमोटो को नियंत्रण करने का मौका मिला और उन्होंने 16–11 की बढ़त बना ली। लेकिन 14–18 से पीछे होने के बाद सेन ने शानदार धैर्य दिखाया, रैलियों को लंबा खींचा, अच्छा बचाव किया और अपने प्रतिद्वंद्वी से गलतियां करवाईं। लगातार पांच अंक ने मैच का रुख बदल दिया जिससे सेन को पहले ही मौके पर गेम खत्म करने का मौका मिला। दूसरा गेम एकतरफा रहा क्योंकि सेन ने समझदारी से रणनीति में बदलाव किया और निशिमोटो को लय नहीं हासिल करने दी। सेन ने अपने मजबूत डिफेंस और सटीक शॉट चयन से 50 मिनट में मुकाबला जीत लिया।

इंडिया ओपन बैडमिंटन : पक्षी की बीट से प्रणय के मैच में रुकावट, आयोजकों की मुश्किलें बढ़ीं

नयी दिल्ली, (भाषा) इंडिया ओपन सुपर 750 में आयोजन संबंधी चिंताओं की सूची बढ़ती ही जा रही है और बृहस्पतिवार को एच एस प्रणय और सिंगापुर के लोह कीन यू के बीच पुरुष एकल के दूसरे दौर के मैच के दौरान 'पक्षी की बीट' के कारण दो बार मैच रोकना पड़ा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे टूर्नामेंट के तीसरे दिन भी असामान्य रुकावटें जारी रहीं। पहले से ही टूर्नामेंट खेलने की स्थितियों, खराब हवा, बहुत अधिक ठंड और इस हफ्ते की शुरुआत में स्टैंड में एक बंदर देखे जाने से जुड़ी शिकायतों के कारण जांच के दायरे में चल रहा है। पूर्व विश्व चैंपियन लोह के खिलाफ प्रणय का मैच पहली बार तब रोका गया जब भारतीय खिलाड़ी पहले गेम में 16–14 से आगे था। निर्णायक गेम की शुरुआत में इसे फिर से रोका गया, जब प्रणय 1–0 से आगे थे। दोनों मौकों पर टूर्नामेंट के अधिकारी कोर्ट एक (मुख्य टीवी कोर्ट) साफ करने के लिए आए। ऐसा लग रहा था कि छत से पक्षी की बीट गिरी थी। प्रणय ने 21–18, 19–21, 14–21 से हार के बाद कहा, ''यह पक्षी की बीट थी जिसने खेल को रोक दिया। '' लोह ने रुकावटों के बारे में बात नहीं की लेकिन प्रदूषण को एक मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, ''हर किसी का स्टैमिना दो स्तर नीचे चला गया है। मौसम अच्छा नहीं है। मेरी सेहत काफी खराब हो गई है। मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूं। जब भी हो सकता है मैं मास्क पहनता हूं। मैं जितना हो सके अंदर रहता हूं, बस यही कर सकता हूं। '' शुरुआत में इन रुकावटों से दर्शक और कमेंटेटर हैरान रह गए क्योंकि चेयर अंपायर ने अचानक अपना हाथ उठाकर खेल रोक दिया। अधिकारियों ने जल्द ही प्रभावित जगह को साफ करने के लिए टिशू और वाइप्स का इस्तेमाल किया। ब्रेक के दौरान जब प्रणय तौलिया लेने गए तो लोह को नेट के पास जाने से पहले छत की ओर देखते हुए देखा गया। दूसरी रुकावट निर्णायक गेम शुरू होने के तुरंत बाद आई, जिसके बाद खेल फिर से शुरू होने से पहले थोड़ी देर सफाई करनी पड़ी। पूर्व भारतीय कोच विमल कुमार स्टैंड से मैच देख रहे थे। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि यह चिड़िया की बीट थी या नहीं, रुकावट सिर्फ 30–40 सेकेंड के लिए थी। उन्होंने फर्श साफ किया। मुझे नहीं पता कि यह चिंता की कोई बड़ी बात है। मैंने अब तक अंदर कोई चिड़िया नहीं देखी है, यह एक छोटी सी बात है। '' उन्होंने कहा, ''चीन को छोड़कर, टूर्नामेंट के 90 प्रतिशत स्थल की हालत बहुत खराब है। '' लेकिन उन्होंने कहा कि साफ–सफाई में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''एक बात यह है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट आयोजित करते हैं तो हमारे पास अच्छी टॉयलेट सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती? स्टेडियम का रख रखाव बहुत जरूरी है। यह भारतीय बैडमिंटन संघ या आयोजकों का काम नहीं है ? '' यह घटना टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की लगातार शिकायतों के बाद हुई है।

नितीश रेड्डी को समय दें, जल्दबाजी में फैसला नहीं करें: पूर्व क्रिकेटर

नयी दिल्ली, (भाषा) पूर्व खिलाड़ियों आकाश चोपड़ा, रॉबिन उथप्पा और मनोज तिवारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जाना चाहिए और क्रिकेट जगत को जल्दबाजी में उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ये प्रतिक्रियाएं राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में रेड्डी के साधारण प्रदर्शन के बाद आई हैं जहां उन्होंने 20 रन बनाए और दो ओवर में कोई विकेट नहीं ले पाए जिससे भारत को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मौके मिलने के बावजूद रेड्डी अक्सर बड़ा प्रभाव डालने में नाकाम रहे हैं।

इन टिप्पणियों से इस युवा खिलाड़ी की भूमिका को लेकर बहस छिड़ गई। उथप्पा ने 'पीटीआई वीडियोज' से कहा, ''ऑलराउंडर बनना आसान नहीं है। आपको दो कौशल में महारत हासिल करनी होती है। रविंद्र जडेजा रातों–रात ऐसे नहीं बने, ना ही हार्दिक पंड्या। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बिताए समय की वजह से पूर्ण खिलाड़ी बने। नितीश रेड्डी को भी उस समय की जरूरत है।''

एमओसी से मंजूरी के बाद नीरज सत्र पूर्व ट्रेनिंग के लिए पोटचेफस्ट्रूम रवाना

नयी दिल्ली, (भाषा) दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने अपने चुने हुए स्थल दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में सत्र पूर्व ट्रेनिंग शुरू कर दी है। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने नए कोच जय चौधरी के साथ उनके 32 दिवसीय शिविर को मंजूरी दे दी है। नीरज ने पिछले हफ्ते चेक गणराज्य के दिग्गज जान जेलेजनी से कोच के तौर पर अलग होने का फैसला किया और चौधरी के साथ जुड़ने का फैसला किया जो उनके शुरुआती कोच थे और इस सुपरस्टार के गृहनगर पानीपत में भाला फेंक के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि यह 28 वर्षीय खिलाड़ी पांच फरवरी तक पोटचेफस्ट्रूम में रहेगा जो दुनिया भर के भाला फेंक के खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख ट्रेनिंग स्थल है और उनके लिए कुल स्वीकृत सहायता राशि 11 लाख 80 हजार रुपये है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) में शामिल एलीट खिलाड़ियों को वित्तीय और साजो–सामान से जुड़ी सहायता पर फैसला करने वाला एमओसी ने बुधवार को यहां बैठक की थी। ट्रेनिंग शिविर में नीरज की सहयोगी टीम में लंबे समय से उनके फिजियोथेरेपिस्ट इशान मारवाहा भी शामिल हैं। सूत्र ने कहा, ''इस ट्रेनिंग शिविर का लक्ष्य इस साल होने वाली प्रमुख प्रतियोगिताओं जिसमें एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल शामिल हैं, से पहले उनकी शारीरिक अनुकूलनता, ताकत और तकनीकी निरंतरता को बेहतर बनाना है।'' उन्होंने कहा, ''स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय सहायता में उनके ट्रेनिंग शिविर का खर्च, जिम और ट्रेनिंग मैदान तक पहुंच, हवाई अड्डे से आना–जाना और जेब खर्च शामिल होगा।'' हरियाणा के इस खिलाड़ी को पिछले साल एडक्टर मांसपेशी में खिंचाव की समस्या थी लेकिन इसके बावजूद वह दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे थे। हालांकि उनके लिए एक बड़ी निराशा पिछले साल सितंबर में तोक्यो विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना था जिसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस समस्याओं को ठीक करने के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया। वह तोक्यो में गत चैंपियन थे लेकिन पूरे मुकाबले के दौरान साफ तौर पर असहज दिखे। उम्मीद है कि नीरज मई में दोहा डायमंड लीग में अपने 2026 सत्र की शुरुआत करेंगे। एमओसी की 167वीं बैठक में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रस्तावों के लिए कुल एक करोड़ 40 लाख रुपये मंजूर किए गए। सूत्र ने बताया, ''इसमें दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में सचिन यादव के लिए विशेष भाला फेंक उपकरण का आग्रह भी शामिल है।'' यादव पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करते हुए नीरज से बेहतर प्रदर्शन किया था। एमओसी की अगली बैठक फरवरी के बीच में होने की उम्मीद है और सूत्रों के अनुसार उस बैठक में कोर और डेवलपमेंट समूह के खिलाड़ियों की मौजूदा सूची की कड़ी समीक्षा की जाएगी। सूत्र ने कहा, ''बुधवार को बैठक ऑनलाइन हुई थी और हालांकि इसी में समीक्षा की जानी थी लेकिन हमने फैसला किया कि खिलाड़ियों की समीक्षा आमने–सामने की बैठक में की जानी चाहिए। इसलिए फरवरी की बैठक महत्वपूर्ण होगी।'' कोर समूह के खिलाड़ियों की संख्या अभी 118 है जिसमें 57 सामान्य और 61 पैरा खिलाड़ी शामिल हैं।

अमन मोखाडे के शतक से विदर्भ विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में

बेंगलुरु, (भाषा) अमन मोखाडे के इस सत्र में पांचवें शतक की बदौलत विदर्भ ने बृहस्पतिवार को यहां गत चैंपियन कर्नाटक को छह विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। मोखाडे ने 122 गेंद का सामना करते हुए 131 रन की पारी खेली। उनके शतक और आर समर्थ (नाबाद 76 रन) के अर्धशतक से विदर्भ ने चार विकेट पर 284 रन बनाकर जीत दर्ज की। कर्नाटक की पूरी टीम 280 रन पर ऑल आउट हो गई थी जिसमें उसके लिए करुण नायर और केएल श्रीजीत ने अर्धशतक जड़े। विदर्भ के तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे (48 रन देकर पांच विकेट) ने कर्नाटक को समेटने में मदद की। अब रविवार को खिताब के लिए विदर्भ का सामना पंजाब और सौराष्ट्र के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। विदर्भ ने देश की 50 ओवर की घरेलू प्रतियोगिता में कर्नाटक को कभी नहीं हराया था और मोखाडे ने एक शानदार पारी खेलकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सलामी जोड़ीदार अथर्व तायडे के जल्दी आउट होने के बाद मोखाडे ने मुश्किल हालात और मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद 101 गेंद में शतक जड़ दिया। उन्होंने ध्रुव शोरे (47) के साथ दूसरे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी निभाई और फिर समर्थ के साथ तीसरे विकेट के लिए 147 रन जोड़े। 20वें ओवर के बाद तेज गेंदबाज वैशाख विजयकुमार को सिर में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा जिससे बीच के ओवरों में कर्नाटक की गेंदबाजी प्रभावित हुई। वैशाख के हेलमेट पर कर्नाटक की पारी के आखिरी ओवर में तेज गेंदबाज यश ठाकुर की गेंद लगी थी जिसके बाद मनवंत कुमार 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' के तौर पर आए। मोखाडे ने तेज गेंदबाज विद्याधर पाटिल की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया और पूरे जोश के साथ जश्न मनाया। चौबीस वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाटिल की गेंद शॉट खेला और सर्कल के अंदर देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट हो गए। इससे पहले कर्नाटक की पारी धीमी गति से शुरू हुई। पहले 10 ओवर में सिर्फ 33 रन बने। टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल को भी खो दिया। फिर करुण और ध्रुव प्रभाकर ने तीसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। प्रभाकर अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन नालकंडे की एक शॉर्ट–पिच गेंद पर पुल शॉट खेला और स्क्वायर लेग पर लपके गए। करुण और केएल श्रीजीत ने चौथे विकेट के लिए 113 रन की भागीदारी निभाई। करुण अपनी टाइमिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे। 34 साल के खिलाड़ी ने 73 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। श्रीजीत ने 54 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। विदर्भ को सही समय पर ब्रेक मिला, जब नालकंडे ने करुण को आउट किया और छह रन बाद श्रीजीत भी आउट हो गए जिससे कर्नाटक का स्कोर पांच विकेट पर 193 रन हो गया। कर्नाटक के लिए श्रेयस गोपाल (36) और अभिनव मनोहर (26) ने योगदान दिया जिन्होंने छठे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। लेकिन घरेलू टीम ने तेजी से कई विकेट गंवा दिए जिससे उनकी लय बिगड़ गई।

बीडब्ल्यूएफ ने आईजी खेल परिसर की समीक्षा की, कहा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए फिट है स्थल

नयी दिल्ली, (भाषा) बैडमिंटन की विश्व संस्था (बीडब्ल्यूएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने इंदिरा गांधी खेल परिसर में सुविधाओं की समीक्षा की है जिसमें इंडिया ओपन का आयोजन हो रहा है और माना कि यह स्थल अगस्त में विश्व चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए सभी जरूरतों को पूरा करता है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के शुरुआती दिनों में हवा के स्तर, बहुत अधिक ठंड, साफ–सफाई और स्थल पर आवारा जानवरों की मौजूदगी को लेकर शिकायतों का साया रहा। खेलने की स्थितियों की आलोचना के बीच बीडब्ल्यूएफ ने एक विस्तृत बयान जारी किया और उसने इन चिंताओं को स्वीकार किया। उसने इस बात को रेखांकित किया कि आयोजन के दौरान कौन से कदम उठाए गए हैं। विश्व संस्था ने बयान में कहा, ''बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने योनेक्स–सनराइज इंडिया ओपन 2026 के दौरान खिलाड़ियों और टीम के साथ मिलकर नयी दिल्ली में इंदिरा गांधी खेल परिसर की स्थितियों की समीक्षा की है। '' उसने कहा, ''जो प्रतिक्रिया मिली वो सकारात्मक और रचनात्मक दोनों हैं और ये इस टूर्नामेंट और भविष्य की चैंपियनशिप के लिए सबसे अच्छा माहौल बनाने में बहुत अहम हैं। हम खिलाड़ियों द्वारा साझा की गई प्रतिक्रियाओं और उसके बाद मीडिया कवरेज को भी स्वीकार करते हैं। '' दानिश खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने स्थितियों को 'स्वास्थ्य के लिए खराब' बताया जिससे सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई और तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठी क्योंकि अगस्त में इसी परिसर में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होना है। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी राजधानी में खेलने की स्थितियों को लेकर चिंता जताई थी जिसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण और ठंड के मौसम से प्रतिभागियों पर असर पड़ रहा था। इन मुद्दों पर बात करते हुए बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि मौसमी कारकों ने चुनौतियां पेश कीं। बयान में कहा गया, ''मुख्य रूप से मौसम की स्थितियों से संबंधित कारकों को प्रबंधित करने ने चुनौतियां पेश की जिसमें धुंध और ठंड का मौसम शामिल रहा जो स्थल के अंदर हवा के स्तर और तापमान को प्रभावित कर रहा है। हालांकि हमारा आकलन इस बात की पुष्टि करता है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर केडी जाधव स्टेडियम की तुलना में महत्वपूर्ण अपग्रेड है जो बेहतर ढांचा प्रदान करता है। '' बीडब्ल्यूएफ ने नए स्थल पर शुरुआती परिचालन कमियों का भी जिक्र किया जिसकी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने आलोचना की थी। उसने कहा, ''सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता के साथ जानवरों को नियंत्रित करने सहित कार्यान्वयन के कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत थी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। '' बीडब्ल्यूएफ ने कहा, ''खिलाड़ियों ने खेलने की सतह और फ्लोरिंग, जिम और मेडिकल सुविधाओं में सकारात्मक सुधारों की बात की है। '' इंडिया ओपन को विश्व चैंपियनशिप से पहले एक अहम परीक्षण टूर्नामेंट के तौर पर देखा जा रहा था और तैयारियों को लेकर चिंताओं ने स्थल की उपयुक्तता पर सवाल खड़े कर दिए थे। बीडब्ल्यूएफ ने दोहराया कि पुराने केडी जाधव स्टेडियम से हटने का मकसद अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना था। बयान में कहा गया है, ''इंदिरा गांधी खेल परिसर में जाने से खिलाड़ियों और अधिकारियों को ज्यादा जगह मिलती है और यह बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीडब्ल्यूएफ की 'फील्ड ऑफ प्ले' की जरूरतों को पूरा करता है। '' बीडब्ल्यूएफ ने भरोसा जताया कि मौजूदा टूर्नामेंट से मिले सबक अगस्त में होने वाली प्रतियोगिता से पहले सुधारों में बदलेंगे। इसमें कहा गया है, ''इस हफ्ते इकट्ठा की गई जानकारी अगस्त में विश्व स्तरीय अनुभव देने के लिए आगे के अपग्रेड में मदद करेगी क्योंकि तब मौसमी समस्याओं के इतने गंभीर होने की उम्मीद नहीं है। '' इसके अनुसार, ''हमारी प्राथमिकता सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुरक्षित, उच्च–गुणवत्ता वाला माहौल सुनिश्चित करना है। हमें विश्वास है कि यह सभी हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम खिलाड़ियों और टीम को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ के साथ साझेदारी में लगातार सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ''

हरलीन का अर्धशतक, मुंबई इंडियंस को हराकर यूपी वॉरियर्स ने चखा पहली जीत का स्वाद

नवी मुंबई, (भाषा) यूपी वॉरियर्स ने हरलीन देओल (नाबाद 64 रन) के नाबाद अर्धशतक की मदद से बृहस्पतिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 11 गेंद रहते सात विकेट से हराकर इस सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। नटाली साइवर ब्रंट (65 रन, दो विकेट) ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हुए तेज अर्धशतक जड़ा जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाए। हरलीन बुधवार को अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद रिटायर्ड आउट हो गई थीं, उन्होंने 39 गेंद की पारी में 12 चौके जड़े और क्लो ट्रायोन (नाबाद 27 रन) के साथ मिलकर टीम को 18.1 ओवर में तीन विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया जिससे यूपी वॉरियर्स की टीम लगातार तीन हार के बाद चौथे मैच में पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं मुंबई इंडियंस की चार मैच में यह दूसरी हार थी। हरलीन ने इच्छानुसार शॉट लगाए जिसमें शबनीम इस्माइल के एक ओवर में तीन चौके भी शामिल थे। इस भारतीय बल्लेबाज ने 15वें ओवर में ऑफ स्पिनर संस्कृति गुप्ता पर स्वीप शॉट से एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हरलीन ने इसी ओवर में दो चौके और जड़े जिससे टीम को 24 गेंद में 29 रन की दरकार थी। हरलीन ने ट्रायोन के साथ मिलकर बिना किसी परेशानी के जीत सुनिश्चित की। हालांकि यूपी वॉरियर्स के लिए शीर्ष क्रम में परेशानी जारी रही जिसमें कप्तान मेग लैनिंग (25 रन) और किरण नवगिरे (10 रन) तेज शुरुआत नहीं करा सकीं।

इससे सात ओवर में यूपी वॉरियर्स का स्कोर दो विकेट पर 50 रन था। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था जिससे हरलीन ने टिककर खेलते हुए टीम को पहली जीत का स्वाद चखाया। हरलीन ने फोबे लिचफील्ड (25 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंद में 73 रन की साझेदारी निभाई। लिचफील्ड के जाने के बाद उन्हें ट्रायोन का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 20 गेंद में 44 रन की अटूट भागीदारी की। नटाली साइवर ब्रंट ने दो जबकि अमेलिया केर ने एक विकेट झटका। इससे पहले मुंबई इंडियंस हालांकि धीमी पिच पर पहले 10 ओवर में रन गति नहीं बढ़ा सकी लेकिन नटाली साइवर ब्रंट ने 43 गेंद की पारी के दौरान नौ चौके और एक छक्का लगाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। अमनजोत कौर (38 रन) और गुणालन कमालिनी (05) स्पिनरों की मददगार पिच पर तेज शुरुआत नहीं करा सकीं। लेकिन सलामी बल्लेबाजों के लगातार ओवरों में आउट होने के बाद नटाली साइवर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर (11 गेंद में 16 रन) जिम्मेदारी से खेलीं। टीम ने पहले 10 ओवर में दो विकेट पर 54 रन बनाए। पर नटाली साइवर ब्रंट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पारी की दिशा ही बदल दी। उनकी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में कामयाब रही जिसमें आखिरी 10 ओवर में 107 रन बने। आशा शोभना की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर हरमनप्रीत के आउट होने के बाद निकोला कैरी (नाबाद 32 रन) ने नटाली साइवर ब्रंट का अच्छा साथ निभाया। नटाली साइवर ब्रंट ने शोभना के ओवर में 17 रन जुटाए जिसमें दो चौके और एक छक्का जड़ा था। यूपी वॉरियर्स के लिए शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और शोभना आशा ने एक एक विकेट झटका।

अंडर–19 विश्व कप: हेनिल के पांच विकेट, भारत ने अमेरिका को छह विकेट से हराया

बुलावायो (जिम्बाब्वे), (भाषा) हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए जिससे भारत ने बृहस्पतिवार को यहां बारिश से प्रभावित आईसीसी अंडर–19 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका को डकवर्थ लुईस पद्धति से छह विकेट से हरा दिया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल ने सात ओवर में एक मेडन के साथ 16 रन देकर पांच विकेट झटके। भारत ने बादलों भरे मौसम में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर हेनिल की शानदार गेंदबाजी से मध्यक्रम को तहस–नहस करते हुए अमेरिका को 35.2 ओवर में महज 107 रन पर ढेर कर दिया। बारिश की बाधा के बाद लक्ष्य 37 ओवर में 96 रन कर दिया गया। जब बारिश आई तब भारतीय टीम ने चार ओवर में एक विकेट पर 21 रन बना लिए थे। इसके बाद अभिज्ञान कुंडू (41 गेंद में नाबाद 42 रन) ने 118 गेंद रहते टीम को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत दिलाई। बारिश के कारण खेल देर से शुरू हुआ। 14 साल के बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी (02) सस्ते में आउट हो गए। उन्हें तीसरे ओवर में ऋत्विक अप्पिडी (पांच ओवर में 24 रन देकर दो विकेट) ने बोल्ड कर दिया। अप्पिडी की लेंथ गेंद पर सूर्यवंशी विकेट से आगे आए और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। कप्तान आयुष म्हात्रे दो चौके लगाकर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे लेकिन तभी बारिश ने एक और रुकावट डाल दी। इस समय भारत को 46 ओवर में सिर्फ 87 रन चाहिए थे। लेकिन लंबे समय तक खेल रुकने के बाद जब फिर शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार समीकरण बदल गया। खेल शुरू होने पर भारत ने म्हात्रे (19) और वेदांत त्रिवेदी (02) के विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए। फिर उप–कप्तान विहान मल्होत्रा 18 रन पर आउट हो गए। इससे पहले हेनिल ने अपने पहले ही ओवर में अमरिंदर गिल को स्लिप में विहान मल्होत्रा के हाथों कैच करवाकर पहला विकेट लिया जिसके बाद तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने साहिल गर्ग (16) को थर्ड मैन पर हेनिल के हाथों कैच करवाकर अमेरिका का स्कोर नौ ओवर में दो विकेट पर 29 रन कर दिया।

प्रियंका गांधी वाद्रा राष्ट्रीय नेता, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं: अजय राय

लखनऊ, (भाषा) कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रियंका गांधी वाद्रा एक राष्ट्रीय नेता हैं और वह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हैं। प्रियंका के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के लिए 100 दिन का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा के बाद राय ने यह टिप्पणी की। राय ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाद्रा प्रदेश में पार्टी के अभियानों में निरंतर प्रमुख रूप से भागीदारी करती रहेंगी हालांकि उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं की जा सकती। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि प्रियंका को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। राय ने कहा, "प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं और वह अकेले उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हैं। लेकिन साथ ही वह उत्तर प्रदेश में पार्टी के सभी अभियानों में प्रमुखता से भागीदारी करती रहेंगी। उत्तर प्रदेश और प्रियंका गांधी दोनों ही पार्टी की योजनाओं में महत्वपूर्ण हैं।" प्रियंका को 2019 में कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया था और उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" पहल सहित कई अभियानों का नेतृत्व किया है और 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने का निर्णय लिया था। हालांकि, पार्टी महज दो सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। राय ने कहा कि इस 100 दिवसीय अभियान के तहत पहली रैली 24 जनवरी को सीतापुर में होगी और पूरे प्रदेश में 30 रैलियों के बाद लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में एक विशाल रैली के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इससे पहले कांग्रेस की विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रियंका के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में पार्टी के 100 दिन की कार्ययोजना की घोषणा की। मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 'मनरेगा' को समाप्त करने जैसे उपायों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

वंदे भारत स्लीपर में नहीं होगी आरएसी, न्यूनतम किराया 400 किमी के लिए लागू होगा : रेलवे बोर्ड

नयी दिल्ली, (भाषा) रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरएसी या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों का कोई प्रावधान नहीं होगा और न्यूनतम 400 किलोमीटर की दूरी के लिये शुल्क लगेगा। रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र में यह जानकारी दी। वंदे भारत ट्रेन के पहले शयनयान संस्करण को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 जनवरी को गुवाहाटी–कोलकाता मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक जनवरी, 2026 को दोनों स्टेशनों के बीच एसी 1, एसी 2 और एसी 3 – तीनों श्रेणियों के लिए संभावित किरायों की घोषणा की थी। नौ जनवरी को जारी परिपत्र में किराया संरचना का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार एक यात्री को एसी 1, एसी 2 और एसी 3 श्रेणियों में क्रमशः 1,520 रुपये, 1,240 रुपये और 960 रुपये का भुगतान करना होगा, चाहे यात्रा की दूरी एक किमी से 400 किमी के बीच कितनी भी हो। परिपत्र के अनुसार, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए, शुल्क की गणना प्रति किलोमीटर के आधार पर की जाएगी, जिसमें एसी 1 के लिए 3.20 रुपये, एसी 2 के लिए 3.10 रुपये और एसी 3 के लिए 2.40 रुपये होंगे। बोर्ड के परिपत्र में कहा गया, "लागू होने पर माल एवं सेवा कर अलग से लगाया जाएगा। न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी 400 किमी होगी। किराया मौजूदा नियमानुसार पूर्णांक (राउंड ऑफ) किया जाएगा। इस ट्रेन के लिए केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। तदनुसार, 'रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन'(आरएसी)/प्रतीक्षा सूची/आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों का कोई प्रावधान नहीं होगा।" इसमें आगे कहा गया है, "समय–समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केवल महिला आरक्षण, दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण, वरिष्ठ नागरिक आरक्षण और ड्यूटी पास आरक्षण ही लागू होगा। इस ट्रेन में कोई अन्य आरक्षण कोटा लागू नहीं होगा।" बर्थ आवंटन के संदर्भ में इसमें कहा गया, "यदि कोई यात्री ऐसे बच्चे के साथ यात्रा कर रहा है जिसके लिए अलग बर्थ की आवश्यकता नहीं है, तो सिस्टम उपलब्धता के आधार पर नीचे की बर्थ आवंटित करेगा। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष यात्रियों और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए, सिस्टम उपलब्धता और सीटों की संख्या के आधार पर स्वचालित रूप से नीचे की बर्थ आवंटित करने का प्रयास करेगा।" इसमें कहा गया, "टिकट रद्द करने के 24 घंटों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, सभी भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। काउंटर पर टिकट खरीदते समय, भुगतान का पसंदीदा तरीका डिजिटल ही होगा। यदि कोई ग्राहक डिजिटल भुगतान करने में असमर्थ है, तो रद्द करने पर रिफंड सामान्य शर्तों के अनुसार किया जाएगा।" अधिकारियों ने कहा कि वाणिज्यिक परिपत्र में मामूली संशोधन हो सकते हैं, जिनका विवरण आम जनता को सूचित किया जाएगा। जब नियमित यात्रियों के लिए ट्रेन के व्यावसायिक संचालन के बारे में पूछा गया, तो अधिकारियों ने कहा कि यह लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हो सकता है, और इसका विवरण एक आधिकारिक परिपत्र के माध्यम से जारी किया जाएगा।

देश सही दिशा और गति के साथ विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगा: सीडीएस जनरल चौहान

नयी दिल्ली, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि देश ''सही दिशा और गति'' के साथ विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये चीजें राष्ट्रों और व्यक्तियों, दोनों को समान रूप से प्रेरित करती हैं। दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट को संबोधित करते हुए, सीडीएस ने सशस्त्र बलों को ''सबसे उत्तम पेशों में से एक'' बताया और युवाओं से राष्ट्र की सेवा करने की अपील की। जनरल चौहान ने कहा, ''जब मैं कहता हूं कि आपका मार्ग और गंतव्य एक ही दिशा में होने चाहिए, तो इसका चयन हमें आज ही करना होगा ताकि आप सही मंजिल तक पहुंचें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप जो भी चयन करें, उसमें राष्ट्रवाद का तत्व भी होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि देश के युवा विकसित भारत की राह में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।सीडीएस ने कहा, ''यह सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि मेरा भी मानना है कि पूरा देश एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हम भी अपने भविष्य की तलाश में हैं। हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, एक समृद्ध राष्ट्र जो सशक्त और सुरक्षित हो।'' उन्होंने कहा, ''2047 में एक विकसित भारत। और मेरा मानना है कि यह हमारा अमृत काल है, और हम एक राष्ट्र के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और, यह हम उन युवाओं की मदद से हासिल करेंगे जो प्रेरित हैं और देश के लिए कुछ करने को तैयार हैं।'' अपने संबोधन में उन्होंने गति के महत्व पर जोर दिया। जनरल चौहान ने कहा, ''मैं इसमें गति का एक और पहलू जोड़ना चाहता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कहावत है... आप कल का इंतजार नहीं कर सकते। एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत कम समय है।'' अपने करियर का उल्लेख करते हुए जनरल ने कहा, ''बहुत समय पहले, लगभग पांच दशक पहले, मैंने यह राह चुनी थी। मैं सशस्त्र बलों में शामिल हुआ। और मैं यहां आप सभी से यही आग्रह करने आया हूं। यह एक ऐसा पेशा है जो इस देश के नागरिकों का सम्मान अर्जित करता है।'' उन्होंने कहा कि यह पेशा युवाओं को एक ''कुलीन'' वर्ग में शामिल होने का अवसर देता है। उन्होंने कहा, ''और जब मैं कुलीन कहता हूं, तो इसका मतलब वेतन और भत्तों से नहीं है, बल्कि उन कौशल से है जिनमें आपको दक्ष किया जाता है। यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। सैन्य सेवा का पेशा बहुत ही सम्मानजनक है।'' जनरल चौहान ने आगाह किया कि आगे का रास्ता हमेशा सुगम नहीं होगा। उन्होंने एनसीसी कैडेट से कहा, ''उतार–चढ़ाव तो आएंगे ही। लेकिन सच्चा सिपाही वही होता है जो इससे हतोत्साहित नहीं होता। हमेशा याद रखना कि रास्ते का मोड़ अंत नहीं होता। आपको आगे बढ़ते रहना है और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी है।''

आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिये नया पोर्टल शुरू

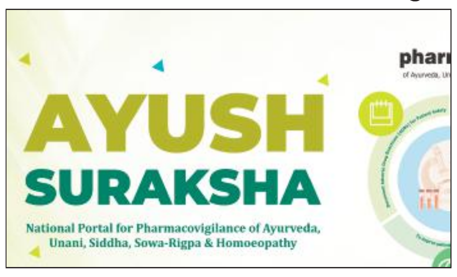

नयी दिल्ली, (भाषा) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 'आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल' की शुरुआत की, जिसके जरिए देशभर के आयुर्वेद शिक्षण संस्थान मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.श्रीनिवास वरखेड़ी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) की अध्यक्ष डॉ. मनीषा कोठेकर ने संयुक्त रूप से पोर्टल की शुरुआत की। इसी के साथ दोनों ने आयुर्वेद गुरुकुलों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देशों को भी जारी किया। बयान के मुताबिक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इस पोर्टल की नोडल एजेंसी रूप में कार्य करेगा और देशभर की संस्थाएं आयुर्वेद गुरुकुलम् के लिये इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसमें कहा गया है कि पंजीकरण, निरीक्षण एवं संबद्धता की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और पूर्णतः डिजिटल बनाया गया है, जिससे गुरुकुल आधारित आयुर्वेद शिक्षा को एक सशक्त राष्ट्रीय नियामक ढांचा प्राप्त होगा।विश्वविद्यालय के कुलपति वरखेड़ी ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन शैली है, जिसकी जड़ें संस्कृत शास्त्रों में निहित हैं। एनसीआईएसएम की प्रमुख डॉ कोठेकर ने कहा कि यह पहल आयुर्वेद में शास्त्रीय प्रामाणिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं पारदर्शिता को नई दिशा देगी। बयान में यह भी जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय नीट की तर्ज पर प्रीदृबीएएमएस (प्रीदृआयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इसी के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और आयुर्वेद गुरुकुलों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपने परिसरों में भी आयुर्वेद गुरुकुल कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत नासिक परिसर सहित दिल्ली और अन्य केंद्रों से की जाएगी। बयान के अनुसार, यह पहल एनसीआईएसएम के प्रीदृआयुर्वेद प्रोग्राम बीएएमएस फ्रेमवर्क के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें कुल सात वर्ष छह माह की समेकित अवधि का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

वैश्विक राजनीति: आखिर अमेरिका को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल लगभग 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर लेकिन आबादी सिर्फ 60 हजार के आसपास। यहां का 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। न घने जंगल, न हाईवे, न चमकते शहर। कई महीनों तक सूरज डूबता नहीं और कई महीनों तक रात खत्म नहीं होती। देखने में शांत, ठंडा और वीरान लगने वाला यह द्वीप आज वैश्विक राजनीति के सबसे गर्म मोर्चों में बदल चुका है। वजह है– अमेरिका की पुरानी लेकिन अब खुली और आक्रामक चाहत। डोनाल्ड ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है–ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में चाहिए लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इस बर्फीले, कम आबादी वाले द्वीप की इतनी ज़रूरत क्यों है और क्या अमरीका इसे हासिल कर पाएगा।सामरिक महत्वग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह स्थित है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच सेतु जैसा काम करता है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पास ही रूस, नीचे यूरोप और पश्चिम में अमेरिका। मतलब साफ है–जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, वह आर्कटिक का चौकीदार बन जाता है। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस– हर मोर्चे पर मुकाबला है। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाती है।ग्रीनलैंड में अमेरिका पहले से मौजूद है। यहां स्थित थुले एयर बेस (अब पिटुफिक स्पेस बेस) अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। यहीं से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है, सैटेलाइट ट्रैक करता है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करता है। अगर अमेरिका को पूरा ग्रीनलैंड मिल जाता है तो वह आर्कटिक का फुल कंट्रोल सेंटर बन सकता है। रूस लगातार आर्कटिक में नए सैन्य ठिकाने, नई पनडुब्बियां, नए एयरबेस और नई मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रूस पर नजर रखने का वॉच टावर है।दुर्लभ खनिजआज की दुनिया मोबाइल, चिप्स, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही है। इन सबकी जान हैं–रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बिना इनके आधुनिक तकनीक ठप हो जाती है लेकिन इन पर अभी चीन का दबदबा है। करीब 60–70 प्रतिशत सप्लाई चीन से आती है। अमेरिका इस निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है और यहीं ग्रीनलैंड अहम हो जाता है। इस द्वीप की धरती के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा खजाना छिपा है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाता है, तो टेक्नोलॉजी की जंग में चीन को सीधी चुनौती मिल सकती है।तेल, गैस और ऊर्जा सुरक्षादुनिया की ऊर्जा भूख खत्म नहीं हुई है। तेल और गैस अब भी वैश्विक राजनीति का ईंधन हैं। ग्रीनलैंड के आसपास समुद्र की गहराइयों में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। अभी बर्फ और मौसम खुदाई में रुकावट हैं लेकिन जैसे–जैसे आर्कटिक पिघल रहा है, ये संसाधन सुलभ होते जा रहे हैं। अमेरिका इसे भविष्य का ऊर्जा बैंक मानकर चल रहा है।आर्कटिक सिल्क रोडग्लोबल वॉर्मिंग सिर्फ पर्यावरण संकट नहीं, यह भू–राजनीतिक बदलाव भी है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एशिया से यूरोप जाने के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। सफर हजारों किलोमीटर छोटा हो सकता है। इस रूट को कहा जा रहा है– आर्कटिक सिल्क रोड ग्रीनलैंड इस रास्ते का प्राकृतिक गेटवे है। जो इस रूट को कंट्रोल करेगा, वह वैश्विक व्यापार की दिशा तय करेगा। अमेरिका यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता।चीन और रूस को रोकने की रणनीतिरूस आर्कटिक में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन निवेश के जरिए पैर जमा रहा है। चीन खुद को नियर–आर्कटिक स्टेट कहता है, भले ही उसका आर्कटिक से सीधा भौगोलिक रिश्ता न हो। ग्रीनलैंड में चीन ने एयरपोर्ट, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कोशिश की। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई तो उसका उत्तरी दरवाजा दुश्मनों के लिए खुल जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, रणनीतिक दीवार है।अमेरिका की पुरानी चाहतग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर नई नहीं है। 1867, 1910, 1946; तीन बार अमेरिका ने डेनमार्क को ऑफर दिया। 1946 में तो 100 मिलियन डॉलर का सोना तक देने को तैयार था। हर बार जवाब मिला दृ ना लेकिन ट्रंप ने डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर सीधी ज़िद पकड़ ली–अगर खरीदा नहीं जा सकता तो दबाव डालो।डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रुखबता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क का साफ संदेश है– ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार, अपनी संसद और अपनी पहचान है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे डरिक्सन ने अमेरिकी प्रस्ताव को बेतुका बताया। ग्रीनलैंड के नेताओं ने कहा–यह जमीन नहीं, हमारी आत्मा है। यूरोप के देशों ने भी डेनमार्क का समर्थन किया। ग्रीनलैंड बिकेगा, इसकी संभावना लगभग शून्य है क्योंकि आज दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, कानून, संप्रभुता और जनमत से चलती है लेकिन दबाव जारी रहेगा– कभी आर्थिक, कभी कूटनीतिक, कभी रणनीतिक।बहरहाल, अमेरिका, चीन और रूस; तीनों की नजरें इसी बर्फीली धरती पर टिकी हैं। बाहर से शांत दिखने वाला ग्रीनलैंड असल में भविष्य की वैश्विक राजनीति का रणक्षेत्र है। यह द्वीप तय करेगा कि आने वाले दशकों में कौन सुपरपावर रहेगा। **राजेश जैन**

सनातन संस्कृति पर बुना षड्यंत्र : त्योहारों की तिथियों का अपहरण

पहले दीपावली के पहले 'नरक चतुर्दशी' कोई उत्सव मनाया जाने वाला दिवस न था। घरों की सफाई आदि के बाद दीवाली को घूर पर दिया जलाया जाता था ताकि वह भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाए और तैयार खाद शुद्ध होकर खेतों में पहुँचे। इधर कुछ वर्षो से हिन्दू पर्व, त्योहार निर्धारित तिथि पर न मनाने की परम्परा सी चल पड़ी है। मुमकिन है कि इसके पीछे बाजार, कारोबारी हित तथा रोजगार पैदा करने की प्रत्याशा हो किन्तु यह पारम्परिक सनातन संस्कृति को विकृत करने का षड्यंत्र और कुचक्र अधिक जान पड़ता है। अयोध्या में दीपावली के पूर्व का 'दीपोत्सव' अनजाने या जान–बूझकर उपर्युक्त शंका की एक बड़ी साजिश लगती है। अब 15 जनवरी को मकर संक्रान्ति का अवकाश इसी की अगली कड़ी है। इसी तरह से पिछले दिनों, सालों में अनेक त्योहार बदली तिथियों में मनाये गये हैं। यह भारतीय सनातन संस्कृति और ब्राह्मणों के ज्ञान, विज्ञान एवं अनुसन्धान को खण्डित करने वाली प्रवृत्ति है। इसके पीछे अफसरशाही का एक तबका हो सकता है जो शिक्षा, सोच, समझ तथा संस्कार से न केवल गुलाम है बल्कि विकृत विदेशी संस्कृति का पिट्ठू और पोषक है।

सुनियोजित कुचक्र: पारम्परिक हिन्दू पञ्चाङ्ग की तिथियों से त्योहारों को खींचकर बाजार की गोद में धकेलने की प्रवृत्ति सनातन धर्म की जड़ों को काटने का सुनियोजित कुचक्र है। नरक चतुर्दशी जो दीपावली से ठीक एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनायी जाती रही, अब पूर्व–दीपोत्सवों के बहाने विकृत हो रही है। यह केवल बाजारवाद नहीं अपितु इसके पीछे अफसरशाही के उस तबके का हाथ है जो विदेशी संस्कृति का दास बनकर स्वधर्म को खण्डित कर रहा है।

पारम्परिक महत्व की उपेक्षा : 'नरक चतुर्दशी' परम्परागत रूप से दीपावली की पूर्व सन्ध्या है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और घरों की सफाई के बाद नकारात्मक ऊर्जा नाश के लिए दीप जलाये जाते थे। अयोध्या में दीपोत्सव को दीपावली से पूर्व (जैसे 2025 में 18–20 अक्टूबर जबकि दीपावली 20–21 को) आयोजित करना शास्त्रीय पञ्चाङ्ग को तोड़ने–मरोड़ने का उदाहरण है। इसी क्रम में मकर संक्रान्ति का अवकाश उत्तर प्रदेश में 14 से 15 जनवरी 2026 को स्थानान्तरित कर दिया गया जो ज्योतिषीय पुण्यकाल से मेल खाता है किन्तु परम्परा से भटकाव दर्शाता है।

बाजार और कारोबार का कुप्रभाव : हिन्दू त्योहार अब बाजार की रणनीति बन गये हैं, जहाँ ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीपावली–नवरात्रि पर ₹12–14 लाख करोड़ का व्यय उत्पन्न करते हैं, 15–30% वृद्धि के साथ। फेस्टिवल सेल्स, मुहूर्त ट्रेडिंग और रोजगार सृजन के नाम पर तिथियाँ बदली जाती हैं, जैसे होली, दशहरा, राखी जो कभी–कभी दो तिथियों पर विभाजित हो जाते हैं। यह व्यावसायिक हित सनातन पञ्चाङ्ग को विकृत कर रहा है, जहाँ सूर्य सिद्धान्त पर आधारित संक्रान्ति जैसे पर्व ग्रेगोरियन कैलेण्डर से 24 दिन विस्थापित हो चुके हैं।

अफसरशाही का विदेशी दासत्व : भारतीय नौकरशाही में औपनिवेशिक विरासत प्रबल है जो नियम–प्रक्रियाओं पर अत्यधिक जोर देकर परिणामों की उपेक्षा करती है और पदानुक्रमित 'एलिटिज्म' को बढ़ावा देती है। सरकारी अवकाश सूचियों में हिन्दू तिथियाँ अक्सर पञ्चाङ्ग से विचलित होती हैं, जैसे जन्माष्टमी या रक्षाबन्धन के राज्यवार भेद। उत्तराखण्ड जैसे प्रयास हिन्दू तिथियाँ जोड़ने के होते हैं, किन्तु केन्द्रीय स्तर पर ग्रेगोरियन प्रभुत्व बना है। यह तबका शिक्षा–संस्कार से विमुख होकर पश्चिमी संस्कृति का पोषक बन गया है, जो सनातन ज्ञान–विज्ञान को 'ब्राह्मण परम्परा' सहित खण्डित कर रहा है।

प्रमाणित आँकड़े और ऐतिहासिक भटकाव : 2026 के सरकारी अवकाशों में 17 राष्ट्रीय छुट्टियाँ हैं, किन्तु हिन्दू पर्वों की तिथियाँ बैंक, शेयर बाजार और स्कूलों के अवकाशों में असंगति है। मकर संक्रान्ति सौर घटना होने पर भी 14 जनवरी पर स्थिर रहती है ग्रेगोरियन से, जबकि चन्द्र–सौर पञ्चाङ्ग लचीला है। अयोध्या दीपोत्सव पर राजनीतिक विवाद उभरा, जहाँ आलोचक इसे विभाजनकारी बताते हैं। पिछले वर्षों में नवरात्रि, दुर्गा पूजा जैसी तिथियाँ बाजार व अवकाश नीतियों से प्रभावित हुईं जिससे सांस्कृतिक विकृति बढ़ी।

शास्त्रीय चेतावनी और प्रतिकार : श्रीमद्भगवद्गीता (3. 35) में स्वधर्म की अडिगता पर जोर हैः "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।" मनुस्मृति और पुराण सूर्य सिद्धान्त पर पञ्चाङ्ग निर्धारित करते हैं, न कि व्यापारिक हितों पर। ब्राह्मणों का ज्ञान–विज्ञान, जो वेद–उपनिषदों से उपजा है, इस कुचक्र से संकट में है। सनातन बन्धुओं को पञ्चाङ्ग पालन, शास्त्रोक्त तिथियों पर अडिग रहना होगा। अफसरशाही के गुलाम तबके को उजागर कर नीतिगत सुधार आवश्यक हैं अन्यथा सनातन संस्कृति का अपहरण पूर्ण हो जाएगा।

डॉ० मत्स्येन्द्र प्रभाकरस्वतंत्र पत्रकार

यूनिटी मॉल परियोजना आर्द्रभूमि क्षेत्र में नहीं है, इसे सब तरह की मंजूरी प्राप्त है: गोवा सरकार

पणजी, (भाषा) गोवा सरकार ने कहा कि चिंबेल में प्रस्तावित यूनिटी मॉल परियोजना अधिसूचित आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र में नहीं आती है और इसे सभी अनिवार्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त है। पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि आर्द्रभूमि संरक्षण प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना जारी कर पुष्टि की है कि उत्तरी गोवा में परियोजना के लिए निर्धारित भूमि अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र की सीमा से बाहर है। खौंटे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रुडोल्फो फर्नांडीस द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, 'रिवोल्यूशनरी गोवन्स पार्टी' के विधायक वीरेश बोरकर, 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' के विजय सरदेसाई और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक वेंजी विएगास सहित विपक्षी दलों ने पर्यावरण के लिए हानिकारक होने का दावा करते हुए परियोजना को रद्द करने की मांग की। मंत्री ने अपने जवाब में कहा, ''सरकार आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र के भीतर विकास कार्यों से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि प्रस्तावित नहीं है और ऐसे निर्माण कार्य किए भी नहीं जा रहे हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण और घरों के ध्वस्तीकरण की संभावना को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए खौंटे ने कहा कि यह परियोजना मौजूदा चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है और यूनिटी मॉल के लिए सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। खौंटे ने कहा कि यूनिटी मॉल से पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों को बुधवार को शाम चार बजे विधानसभा में अपने कक्ष में आमंत्रित किया, ताकि उनसे मिलकर उनकी चिंताओं पर चर्चा की जा सके। हालांकि, विपक्षी सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं थे और अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गणेश गांवकर ने सत्र को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

संपादकीय

सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंसः सुरक्षा, सहयोग और भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम

सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस उस व्यापक दृष्टि को रेखांकित करना है जिसमें आज की दुनिया सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और सहयोग को एक साझा लक्ष्य के रूप में देख रही है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने यह सिद्ध कर दिया कि जब विचार, अनुभव और जिम्मेदारी एक मंच पर एकत्र होते हैं, तब केवल समाधान ही नहीं निकलते, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय होती है। यह सम्मेलन महज़ एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक जीवंत संवाद था, जहाँ चिंतन, नवाचार और व्यावहारिक अनुभवों का अद्भुत संगम देखने को मिला।आज का युग डिजिटल परिवर्तन का युग है। हर संस्था, हर सरकार और हर नागरिक किसी न किसी रूप में तकनीक पर निर्भर है। ऐसे समय में सुरक्षा और गोपनीयता केवल तकनीकी शब्द नहीं रह जाते, बल्कि सामाजिक विश्वास की नींव बन जाते हैं। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने इसी मूल भावना को केंद्र में रखा। इस मंच ने यह स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा या संगठनात्मक सुरक्षा केवल आईटी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व, नीति–निर्माण और संगठनात्मक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सम्मेलन में व्यक्त विचारों ने यह संदेश दिया कि सुरक्षा को लागत के रूप में नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें केवल चुनौतियों की चर्चा नहीं हुई, बल्कि समाधान और संभावनाओं पर भी गहराई से विचार किया गया। वक्ताओं और प्रतिभागियों के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ कि चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा, सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी, सभी को समान रूप से बदलते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने इन विविध अनुभवों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहाँ प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग ने ली। यह सहयोग ही आज की जटिल समस्याओं का सबसे प्रभावी उत्तर है। सम्मेलन का माहौल अत्यंत सकारात्मक और प्रेरणादायक रहा। यहाँ डर या असुरक्षा की भावना के बजाय तैयारी और आत्मविश्वास का स्वर प्रमुख था। यह स्वीकार किया गया कि जोखिम हमेशा रहेंगे, लेकिन सही रणनीति, सही लोग और सही सोच के साथ उन्हें काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने यह विश्वास जगाया कि यदि संगठन समय रहते सीखने और बदलने को तैयार हों, तो कोई भी चुनौती असाध्य नहीं है। इस आयोजन की एक और विशेषता यह रही कि इसमें तकनीकी और गैर–तकनीकी दृष्टिकोणों के बीच की दूरी को कम किया गया। अक्सर सुरक्षा से जुड़े विषयों को अत्यधिक तकनीकी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शीर्ष प्रबंधन या नीति–निर्माताओं के लिए उन्हें पूरी तरह समझ पाना कठिन हो जाता है। लेकिन इस सम्मेलन में संवाद की भाषा सरल, व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण रही। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा केवल विशेषज्ञों का विषय नहीं है, बल्कि हर निर्णयकर्ता को इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने नेतृत्व की भूमिका को विशेष महत्व दिया। यह बार–बार रेखांकित किया गया कि मजबूत सुरक्षा ढांचा केवल तकनीक से नहीं बनता, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व से बनता है। जब नेतृत्व सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, तभी संगठन के हर स्तर पर उसकी गंभीरता समझी जाती है। सम्मेलन में साझा किए गए अनुभवों ने यह दिखाया कि जिन संस्थाओं में शीर्ष स्तर से स्पष्ट समर्थन मिलता है, वहाँ सुरक्षा उपाय अधिक प्रभावी और टिकाऊ होते हैं। यह सम्मेलन ज्ञान साझा करने का भी एक सशक्त माध्यम बना। अलग–अलग क्षेत्रों से आए पेशेवरों ने अपने अनुभव, सफलताएँ और कभी–कभी अपनी विफलताएँ भी खुले मन से साझा कीं। इस खुलेपन ने सम्मेलन को और अधिक विश्वसनीय और उपयोगी बनाया। इससे यह संदेश गया कि गलतियों को छिपाने से नहीं, बल्कि उनसे सीखने से ही प्रगति संभव है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने सीखने की इसी संस्कृति को प्रोत्साहित किया। आज जब दुनिया तेजी से आपस में जुड़ रही है, तब एक क्षेत्र में हुई घटना का प्रभाव सीमाओं से परे चला जाता है। इस संदर्भ में सम्मेलन ने वैश्विक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर हुई चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा एक वैश्विक जिम्मेदारी है। हालांकि प्रत्येक देश और संगठन की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी मूल सिद्धांत साझा किए जा सकते हैं। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने इसी साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। इस आयोजन का सकारात्मक प्रभाव केवल सम्मेलन कक्ष तक सीमित नहीं रहा। यहाँ से निकले विचार और चर्चाएँ प्रतिभागियों के साथ उनके संगठनों तक पहुँचीं और वहाँ आगे की बातचीत का आधार बनीं। इस तरह, सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन गया, न कि एक बार का आयोजन। यह इसकी सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। सम्मेलन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य की चुनौतियाँ केवल तकनीकी नहीं होंगी, बल्कि मानवीय और नैतिक प्रश्न भी सामने आएंगे। डेटा की गोपनीयता, डिजिटल अधिकार और जिम्मेदार तकनीकी उपयोग जैसे विषयों पर हुई चर्चाओं ने यह दिखाया कि सुरक्षा का संबंध सीधे समाज से है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर यह साबित किया कि वह केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि भविष्य की भी चिंता करता है। कुल मिलाकर, सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मंच बनकर उभरा जिसने आशा, सहयोग और तैयारी का संदेश दिया। इसने यह विश्वास मजबूत किया कि चुनौतियाँ चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हों, सामूहिक प्रयास, ज्ञान साझा करने और सकारात्मक सोच से उनका सामना किया जा सकता है। आज के अनिश्चित और तेजी से बदलते समय में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यह सम्मेलन हमें यह याद दिलाता है कि सुरक्षा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में रुकना नहीं, बल्कि निरंतर सीखते और आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। सीएसपीओसी कॉन्फ्रेंस ने इस यात्रा को दिशा दी है और यह उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में इससे जुड़े प्रयास और भी अधिक मजबूत, समावेशी और प्रभावी होंगे। यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी सबसे सकारात्मक पहचान है।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

प्रकृति विज्ञान के धरातल पर नवदुर्गाओं के दर्शन

देवी माहात्म्य अर्थात दुर्गा सप्शती का पाठ व श्रवण करने से सभी मनुष्यों पर मेरी कृपा दृष्टिबनी रहती है। दुःख, बाधाएं शांत हो जाती हैं और सुख–समृद्धि का एक नया वातावरण जन्म लेता है। दुर्भाग्यवश प्रकृति विज्ञान की पश्चिमी सोच ने दुर्गा सप्तशती के इस विचार को पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में उपेक्षित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति पूजक भारत जैसे देश में भी तरह–तरह की प्राकृतिक और राजनैतिक आपदाएं विस्फोटक होती जा रही हैं और प्रकृति विरोधी मधु कैटभ भी प्रकृति को दासी बनाने पर तुले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरण प्रदूषण का महिषासुरी आक्रमण प्रकृति की सभी शक्तियों को चुनौती देने में लगा है। हवा, पानी, धरती, आकाश आदि इन सभी प्राकृतिक शक्तियों पर राज करने की हवस बढ़ती जा रही है और पर्यावरण प्रदूषक असुर विनाशकारी अस्त्र–शस्त्रों से प्रकृति परमेश्वरी के साथ युद्ध की तैयारी में जुट गये हैं। इसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय शक्ति पूजा का पूरी दुनिया को यह संदेश है कि शारदीय नवरात्र को महज एक धार्मिक पर्व ही न माना जाये, बल्कि इसे प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाये। भारत का यह राष्ट्रीय धर्म हो जाता है कि वह प्रकृति पूजा के पर्यावरण विज्ञान पर खुद अमल करे और विनाशकारी भौतिक विज्ञान के दुष्परिणामों से झुलसे अन्य देशों को भी गुमराह होने से बचाए। जागरूक रखने के लिए भारत के प्रकृति वैज्ञानिकों ने विश्व को 'दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत जैसे दो अमूल ग्रंथरत्न दिये। चिंता का विषय यह भी है कि पश्चिमी पर्यावरण विज्ञान की सोच ने भारतीय प्रवृत्ति की पूरी अवधारणा को कुंठित कर दिया है। उपभोक्तावाद और अंधविकासवाद के आक्रमणों से आज प्रकृति तनाव के दौर से गुजर रही है।

प्रकृति का मातृभाव से पूजनः भारतीय चिंतक प्राचीनकाल से ही शक्ति पूजा के माध्यम से प्रकृति विज्ञान के गूढ़ रहस्यों से मानव समाज को अवगत कराता आया है। नवरात्र के अवसर पर प्रकृति को मातृभाव से पूजने का यही अर्थ है कि सृष्टिको नियमन करने वाली प्रकृति परमेश्वरी से हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सके। **मार्कण्डेय ऋषि को भी यह चिंता थी कि प्रकृति विज्ञान के धरातल पर भी मनुष्य नवदुर्गाओं के दर्शन कर सके। देवी कवच में जिन नौ दुर्गाओं के नाम आए हैं, वे इस प्रकार हैं–**

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चंद्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्॥
पचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यानीति च।
सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्।
नवनमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः॥

प्रथम शैलपुत्रीः पर्यावरण संतुलन की दृष्टिसे पर्वत राज हिमालय की प्रधान भूमिका है। यह पर्वत मौसम नियंता होने के साथ–साथ देशवासियों को राजनैतिक सुरक्षा और आर्थिक संसाधन भी मुहैया करता है। प्राचीनकाल से ही हिमालय क्षेत्र ने धर्म और संस्कृति के विभिन्न स्रोत भी प्रवाहित किये। हिमालय क्षेत्र के इसी राष्ट्रीय महत्व को उजागर करने के लिये ही देवी के नौ रूपों में 'शैलपुत्री के रूप में स्मरण करके सर्वप्रथम स्थान दिया गया है।

द्वितीय ब्रह्मचारिणी : देवी का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। इस देवी को प्रकृति के सच्चिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में अम्भृण ऋषि की पुत्री वाग्देवी ब्रह्मस्वरूपा होकर समस्त जगत को ज्ञानमय बनाती है और अपने रुद्रबाण से अज्ञान का विनाश करती है–

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शखे हन्तवा उ।
अहं जनाय समदं कृष्णोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश।।

तृतीय चंद्रघण्टेतिः देवी की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। सुवर्ण सदृश शरीरवाली इस देवी के तीन नेत्र और दस हाथ हैं। मस्तक में घंटा के आकार का अर्द्धचंद्र विद्यमान रहने के कारण चंद्रघण्टा कहा जाता है। शस्त्र–अस्त्र से सुशोभित सिंहवाहिनी यह देवी प्रकृति विनाशक दैत्यों का संहार करने के लिये प्रहरी का दायित्व संभालती हैं किन्तु प्रकृति उपासकों के लिए यह अपना लावण्यमयी दिव्य रूप उद्भासित करती हैं, इसलिए सप्तशती के टीकाकारों ने इसे प्रकृति के आल्हादक और सौंदर्यमय शक्तित्व के रूप में परिभाषित किया है।

कूष्माण्डेति चतुर्थकम्ः चौथी दुर्गा का नाम कूष्माण्डा है। किंचित हास्य मुद्रा में अण्ड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण यह शक्ति कूष्माण्डा कहलाई। सूर्य मंडल में निवास करने वाली इस देवी की ऊर्जा दसों दिशाओं में व्यापक रहती है। सिंहवाहिनी, अष्टभुजा यह देवी अस्त्र–शस्त्रों से सुसज्जित रहती है। कुम्हड़े की बलि प्रिय होने के कारण भी यह कूष्माण्डा के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिविधा आपदाओं का संचालन तंत्र प्रकृति के इस चौथे रूप में समाया हुआ है, इसलिए उत्तरांचल के ग्रामों में नवरात्र के अवसर पर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुम्हड़े की बलि देने की प्रथा आज भी है।

पंचम स्कन्दमातेतिः पांचवीं दुर्गा का नाम स्कन्दमाता है। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद शिव से विवाह किया और बाद में स्कंद इनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। पौराणिक मूर्ति विज्ञान के अनुसार इस देवी की तीन आंखें और चार भुजाएं हैं। पद्मासना इस देवी की गोद में स्कंद नामक बालक विराजमान है। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में स्कंदमाता प्रकृति को माता के समान देखने का ज्ञान प्रदान करती हैं।

अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वियाः का प्रकृति दर्शन ही देवी के इस पौराणिक चरित्र में साकार हुआ है। नवरात्र के शुभागमन पर देव्यपराध क्षमापन स्त्रोत के माध्यम से हर वर्ष स्कंदमाता का ध्यान करते हुए भारत का प्रकृति विज्ञानी यही कामना करता है कि हे जगजननी प्रकृति माता! मनुष्य जाने या अनजाने स्वार्थवश, प्रकृति के प्रति अपराध करता रहता है परन्तु आप अपने इन कुपुत्रों के अपराध क्षमा कर दो। कारण यह है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती।

तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे।
कुपुत्रों जायते कचिदपि कुमाता न भवति॥

षष्ठं कात्यायनीतिः कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर छठी दुर्गा पुत्री रूप से कात्यायन आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए कात्यायनी कहलाई। यह भी प्रसिद्ध है कि वृन्दावन की गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी के तट पर कत्यायनी की पूजा की थी। इससे यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। तीन नेत्र और आठ भुजाओं वाली इस देवी का वाहन सिंह है।

तपोवन संस्कृति के जरिये पर्यावरण संरक्षणः सर्वविदित है कि तपोवन संस्कृति का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिसे महान योगदान रहा है। अभिज्ञान शाकुन्तल के अनुसार कण्व आश्रम में भी तपोवनवासी शकुन्तला के नेतृत्व में संस्कृति संरक्षण व संवर्धन का जो कार्यक्रम चला रहे थे, वह आज के पर्यावरण संरक्षकों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है। उपभोक्ताभाव के मूल्यों से परे हटकर पर्यावरण प्रेमी शकुन्तला का यह नियम था कि वह तपोवन के पेड़–पौधों को जल दिये बिना पहले जल ग्रहण नहीं करती थी। आभूषण की शौकीन होने पर भी तपोवन की वनसंपदा का सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग नहीं करती थी। वनस्पतियों में पहली बार जब पुष्पोदगम् होता था तो पूरा तपोवन उत्सव मनाता था। प्रकृति का कात्यायनी रूप वस्तुतः प्रकृति के सुकुमार और नित्यकुमारी रूप का परिचायक है। प्रकृति के साथ गंधर्व विवाह के उपभोक्तावादी नारी मूल्यों के विरुद्ध इस शक्ति तत्व की यह विशेषता भी है कि पुरुषायत्त समाज व्यवस्था के विरुद्ध जाकर भगवती कात्यायनी पति की दासता का त्याग कर देती है और तपोवन प्रकृति के समान नित्य कौमार्य रूप का वरण कर लेती है। नारी स्वातंत्र्य 'कात्यायिनी का प्रधान चरित्र है–

देव कामार्थ कात्यायनाभमे आविर्भूता तेन
कन्यात्वेन स्वीकृतेति कात्यायनीति नाम भहवत्याः।
अभ्या निरंतर कुमारीत्वेन पन्यधीनतया
स्वतंत्रत्वम्।। (दुर्गा सप्तशती)

सप्तमं कालरात्रीतिः दुर्गा की सातवीं शक्ति 'कालरात्रि है। इसे महाकाल आदि की शक्ति 'काली या 'महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र की सातवीं तिथि को इस कालरात्रि का विशेष स्तवन किया जाता है। प्रलय तथा विध्वंस के प्राकृतिक प्रकोप देवी के इसी भयावह रूप की अभिव्यक्ति है। कालरात्रि की आकृति विकराल है। यह महाकाली मुर्दे पर सवार है। उसका चेहरा तीक्ष्ण दांतों और दहशत भरे हास्य से जगत को कंरकपा कर देता है। जिह्वा बाहर निकाले श्मशानवासी इस देवी के एक हाथ में खड्ग और दूसरे में नरमुण्ड रहता है। तीसरे हाथ में अभयदान की मुद्रा रहती है तो चौथा हाथ वरदान देने के भाव से ऊपर उठा रहता है।

महागौरीति चाष्टमम्ः 'काली के भयावह रूप से शिव भी स्तब्ध रह गये थे, तब उन्होंने इस देवी को आक्रोश से 'काली कह दिया। इस पर प्रकृति ने अपने इस भयावह रूप से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या की और स्वयं को गौरवपूर्ण बना दिया। देवी का यह आठवां रूप 'महागौरी–के नाम से लोकविश्रुत है। सत्यम्–शिवम्–सुन्दरम् को व्यक्त करने वाली इसी सौम्य और सात्विक प्रकृति की मुद्रा की लोककामना की जाती है, इसलिए दुर्गाष्टमी के दिन इसी लोक कल्याणी महाशक्ति की पूजा का विशेष अनुष्ठान होता है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली प्रकृति सत्वगुण प्रधान है। सर्जनहारी प्रकृति के संरक्षण से लोक कल्याण संभव होता है। इसी ने पूर्व काल में शुम्भ नामक दैत्य का संहार किया और यही साक्षात सरस्वती भी है–

गौरी देहात्समुद्भूता या सत्वैक गुणाश्रया।
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुष्भासुर निर्वहिणी॥

नवमं सिद्धिदात्रीः दुर्गा की नौवीं शक्ति 'सिद्धिदात्री कहलाती है। विश्व के सभी कार्यों को साधने वाली देवी के इस रूप को सर्वार्थसाधिका प्रकृति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। ऋग्वेद की ब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी स्वयं कहती हैं कि मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूं, उसे सर्वश्रेष्ठ बना दूं और सर्वज्ञान संपन्न बृहस्पति बना दूं। (ऋग्वेद 10–125–5) देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इसी शक्ति की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं और वे अर्द्धनारीश्वर कहलाये। सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा यह देवी प्रसन्न वंदना है। दुर्गा के इस स्वरूप की देव, ऋषि, सिद्ध, योगी, साधक व भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं।

विकसित @2047 के लिए युवा

विकसित भारत की संकल्पना युवाओं के रचनात्मक कार्य क्षमता एवं रचनात्मक संरचनात्मक ऊर्जा से ही संभव है । भारतवर्ष वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र हैं जिसमें देश की 28.2% यानी 40 करोड़ आबादी ' 15– 29' आयु – वर्ग की हैं । यह आयु – वर्ग नवाचार ,विकास, ग्राहय एवं अधिगम के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त आयु होती है। राष्ट्र के इस ऊर्जावान युवा वर्ग में राष्ट्र के उत्थान एवं प्रत्येक भारतीयों के जीवनस्तर को गुणात्मक बनाए रखने की क्षमता, धारिता, और योग्यता होती है। युवाओं के सक्रिय भागीदारी एवं ऊर्जावान दक्षता से राष्ट्र को सामाजिक ,आर्थिक, एवं राजनीतिक(राजनैतिक) समृद्धि के लिए उत्प्रेरित करने की अनंत ,असीमित ,अपार एवं असीम क्षमता होती है। युवाओं को बौद्धिक ईमानदारी, सामाजिक समावेशिता, राष्ट्रीय जिम्मेदारी एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। इनके शिक्षा का उद्देश्य ' आत्मनिर्भर' बनना है। युवाओं की संकल्प, संकल्पित क्षमता, ऊर्जा एवं नवाचार के द्वारा "विकसित भारत@2047" को प्राप्त कर लेंगे। भारत के युवाओं में इस संकल्प को साकार करने की असीमित क्षमता है। देश के युवाओं में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं बौद्धिक विमर्श का जीवंत क्षमता है। विकसित भारत के निर्माण के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता एवं समर्पण असाधारण हैं। नवीन विचारों को ग्राह्म करने की युवाओं में अपार संभावनाएं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा शक्ति समर्पित है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉलेजों, एवं स्कूलों में ' युवा संगम ',' विमर्श संगोष्ठी' ,' व्याख्यान श्रृंखलाएं' एवं ' नेतृत्व क्षमता अभ्यास कार्यक्रम ' होने से युवाओं में अभिप्रेरणा ,उनमें इन कार्यक्रमों के प्रति मनोबल, ऐसे व्याख्याताओं की तरह बनने की ललक एवं नेतृत्व क्षमता अभ्यास के द्वारा व्यक्तित्व– निर्माण के लिए अपार संभावनाएं होती हैं जो युवाओं के ऊर्जा को बौद्धिक क्षितिजीकरण करके चरित्र – निर्माण ,व्यक्ति – निर्माण एवं राष्ट्र– निर्माण में प्रेरित करते हैं। इन सकारात्मक प्रयासों के संकलित प्रभाव से युवाओं में विकास भावना को उन्नयन करने में सहयोग ली जा रही है जो भविष्य में एक प्रकार से सतत विकास की मानवीय पूंजी सृजित करता है। इन शैक्षणिक निकायों से ऊर्जावान उद्दीपक निकालकर समाज, राज्य ,एवं राष्ट्र में सकारात्मक योगदान करते हैं । भारत असीम, अपार, एवं असीमित संभावनाओं का राष्ट्र हैं,जिससे समय–समय पर ऊर्जावान नेतृत्व निकलते हैं, जो देश एवं काल में राष्ट्र में महनीय भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को विकसित भारत के निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित करके उनके ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है।

युवाओं की नेतृत्व एवं भागीदारी समाज के विकास व राष्ट्र – निर्माण में सक्रिय सहभागिता एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उन्नयन करने के लिए अतिमहत्वपूर्ण होती है। युवा नवीनता एवं परिवर्तन की अत्यधिक ऊर्जा रखते हैं जिससे सामाजिक समस्याओं के समाधान, सामाजिक समस्याओं के समाधान के वाहक, सामाजिक परिवर्तन के चालक एवं प्रेरणादायक व प्रभावशाली भूमिका प्रदान करते हैं। भारत के युवा आबादी भारत की बड़ी मानवशक्ति हैं, जो समस्याओं के समाधान के प्रति नवोन्मेष दृष्टि अपनाते हैं। युवाओं के भीतर उत्साह व कार्य करने का जुनून होता है, उनके भीतर परिश्रम करने की क्षमता होती है, सपने साकार करने का मनोबल होता है। उनके कार्य के परिणाम से मिली सफलता देश की सफलता होती है। देश ने विगत 11 वर्षों से "विकसित भारत @2047"का संकल्प लिया है। इसकी संपूर्ति में सबसे ज्यादा योगदान युवाओं की है। युवाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत की प्राथमिकता है।

2024 में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 1213 हो गई है। यह विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के बेहतर एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए हुआ है। उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 59000 हो गई है जिससे अधिकांश युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बेहतरीन संस्थाएं उपलब्ध हो रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन हुआ है । मेडिकल कालेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है और मेडिकल सीटों में 130% की वृद्धि हुई है। आईआईटी और आईआईएम की संख्या भी क्रमशः 23 एवं 20 हो गए हैं जिससे शीर्ष स्तर की शिक्षा तक पहुंच सरल हो गया है। इस तीव्र बदलाव का परिणाम हुआ है कि नूतन पीढ़ी के तकनीशियन ,प्रबंधन विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ प्राप्त हुए हैं जो राष्ट्र की सेवा लगन से कर रहे हैं । भारतीय विश्वविद्यालय फै रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा वैज्ञानिकों ने नवोन्मेष व विकास में नूतन योगदान दे रहे हैं। अद्यतन में कानपुर आईआईटी के युवा वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात के लिए महत्वपूर्ण एवं ऊर्जावान प्रयास करके समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। अतीत से वर्तमान समय तक युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका में सक्रिय सहयोग दिया है। युवा देश के विकास में ईमानदारी से कार्य कर रहे है जो देश के विकास में उनकी भूमिका का संकलन है। युवाओं का इस समाज व देश के प्रति संकल्पित सामाजिक जिम्मेदारी है, जिनको संपूरित करना उनका नैतिक कर्तव्य है। नूतन ऊर्जा से भरा सकारात्मक चिंतन एवं चरित्रवान अवयव से देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहे है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण आबादी से ज्यादा युवा आबादी रहती है। युवा देश के ईमानदार प्रत्याशी चुनकर सभ्य नागरिक समाज के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकते है। राष्ट्र– निर्माण में युवाओं की भूमिका सराहनीय एवं मूल्यवान रहा है। युवाओं का योगदान रोजगार के अवसरों का सदुपयोग करके भारत को वैश्विक स्तर पर एक कुशल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में है। नूतन सोच व भरपूर ऊर्जा के साथ सामाजिक समस्याओं को हल करना, नवोन्मेष,नवाचार एवं तकनीकी कौशल का अनुप्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय सहयोग करना है। लैंगिक विषमता को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहयोगी होना युवाओं के सामाजिक आभार का घटक है।भारत में नवाचार संस्कृति में गुणात्मक वृद्धि हुआ है। जुलाई, 2025 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.63 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें 45% महिलाएं भी हैं। इसके अंतर्गत डिजिटल कौशल, हरित तकनीकी, एआई ,एवं रोबोटिक्स जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य है कि 2026 तक 4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देकर "आत्मनिर्भर भारत" निर्माण में सहयोग करना है। भारत के युवाओं ने अपने रचनात्मक ऊर्जा एवं कौशल से विकसित भारत के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं । इनकी भूमिका सामाजिक क्षेत्र ,राजनीतिक क्षेत्र,एवं अन्य क्षेत्रों में सराहनीय है। अपने शारीरिक परिश्रम एवं नवोन्मेषी सोच से विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हो सकता है।

लेखक सामयिक विषयों एवं इतिहास पर गंभीर पकड़ रखते हैं।इनका निम्न सुझाव हैः–

1. युवाओं के भीतर नवोन्मेष,नवाचार एवं विकास के प्रति गंभीर अवधारणा होती है। 2. भारत में ' जेन जी' अपने रचनात्मक ऊर्जा को संरचनात्मक पहलुओं में अनुप्रयोग कर रहे हैं। 3. युवा वर्ग अपने कार्यदाई क्षमता एवं पहलकारी कार्यों से भारत को नवीनता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। 4. सामाजिक क्षेत्रों,आर्थिक क्षेत्रों एवं राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं का अवदान उच्चतर स्तर का है।

डॉ. बालमुकुंद पांडे
राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन

टॉक्सिक में धूम मचाएंगी तारा सुतारिया, ब्रेकअप की खबरों पर बटोरी सुर्खियां

तारा सुतारिया बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। शुक्रवार को तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया से ब्रेकअप की खबरें आती रहीं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो ये स्टार कपल ही जानता है। लेकिन इन सभी के बीच तारा अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर भी चर्चा में हैं जिसमें दमदार किरदार के साथ बड़ी स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। यश की एक्शन से भरपूर फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन–अप्स' से तारा सुतारिया का पहला लुक बीते दिनों रिलीज हुआ था। डायरेक्टर गीतु मोहनदास की इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी भी अहम भूमिकाओं में हैं। तारा फिल्म में रेबेका का किरदार निभा रही हैं। पोस्टर में, वह हाथ में रिवॉल्वर लिए एक रहस्यमय रेट्रो लुक में नजर आ रही हैं। उनके किरदार के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आकर्षक और सुरुचिपूर्ण रेबेका सत्ता और हथियारों को अपने जन्मसिद्ध अधिकार की तरह इस्तेमाल करती है, उसमें आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति है। रेबेका के किरदार में तारा सुतारिया के बारे में बात करते हुए गीतु मोहनदास ने कहा कि मुझे हमेशा से तारा की रक्षा करने का सहज प्रेम रहा है। शायद इसलिए कि वह एक संकोची आत्मा हैं या शायद यह वह कवच है जिसके साथ वह सहज महसूस करती हैं। और शायद इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में ही महसूस किया कि उन तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें दबाव डालना या उनसे अधिक की मांग करना नहीं, बल्कि उन्हें सहजता से रहने की जगह देना है। इस निर्णय ने हमारे संबंधों को आकार दिया, जो शांत, अत्यंत पेशेवर और पूरी तरह से सुसंगत साबित हुआ। इसके साथ ही तारा इन दिनों अपने ब्रेकअप और एपी ढिल्लों के साथ कॉन्सर्ट को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। तारा सुतारिया और वीर पहारिया के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह एपी ढिल्लों हैं। मुंबई में हुए कॉन्सर्ट के दौरान 'एक्सक्यूज़' गाने वाले वीर पहारिया द्वारा तारा को गले लगाने और किस करने के कुछ ही दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ है। हालांकि 'टॉक्सिक' फिल्म की अभिनेत्री ने पहले वीर के साथ अपने रिश्ते को लेकर फैली सभी नकारात्मक बातों को खारिज कर दिया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद अब सभी को लग रहा है कि कॉन्सर्ट विवाद ही ब्रेकअप का कारण है। नतीजतन, एपी ढिल्लों अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। एपी ढिल्लों एक्स पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं और नेटिज़न्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुंबई शो के दौरान उनके किए गए व्यवहार की वजह से तारा और वीर का ब्रेकअप हुआ। एक यूजर ने दावा किया कि अफवाहें बढ़ती गईं। दबाव बढ़ता गया। रिश्ता टूट गया। उसने आगे पूछा कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर गलती किसकी थी? एक अन्य यूजर ने तारा, वीर और एपी की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर करते हुए लिखा कि तारा ने ढिल्लों के साथ डांस करना शुरू किया और उन्हें किस किया। सोशल मीडिया पर इसे उनके ब्रेकअप का कारण बताया जा रहा है।

पुरानी अंगूरी भाभी की बेटी को देखा? हीरोइन से कम नहीं हैं शुभांगी अत्रे की लाडली आशी, फैन बोले– '19–20 का फर्क है'

शुभांगी अत्रे ने टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए घर–घर में पहचान बनाई। उन्होंने इस चर्चित शो में 10 साल तक काम किया और अंगूरी भाभी बनकर दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन, अब शो के पहले सीजन के खत्म होने के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया। अब उनकी जगह शो में शिल्पा शिंदे ने ले ली है, जो पहले भी अंगूरी भाभी का किरदार निभा चुकी हैं। लेकिन, मेकर्स के साथ हुई अनबन के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था। दूसरी तरफ शुभांगी अत्रे भले ही इस शो से दूर हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी छाई रहती हैं। साड़ी पहने, भोली–भाली अंगूरी भाभी के किरदार से दर्शकों के दिल जीतने वालीं शुभांगी अत्रे रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं और इस मामले में अपनी टीनएज बेटी आशी को भी भारी टक्कर देती हैं।

शुभांगी अत्रे की बेटी आशीः जी हां, पुरानी अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे की एक बेटी भी हैं, जिनका नाम आशी है। एक्ट्रेस ने पियूष पूरे से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी आशी हुईं। शुभांगी, पियूष पूरे से पिछले साल ही अलग हुई थीं। वहीं तलाक के बाद पीयूष का निधन भी हो गया। लेकिन, अब सोशल मीडिया पर आशी के साथ शुभांगी अत्रे की कुछ तस्वीरें चर्चा में हैं, जिन्हें देखकर यूजर्स का कहना है कि आशी को भी फिल्मों में अपना करियर जरूर आजमाना चाहिए।

19 साल की हैं आशीः शुभांगी अत्रे की बेटी आशी 19 साल की हैं और विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन, एक्ट्रेस के फैंस का कहना है कि उन्हें देखकर बिलकुल नहीं लगता कि वह 19 साल की बेटी की मां हैं।

कई ने उन्हें संतूर मम्मी का टैग दिया तो कई का कहना है कि उनमें और उनकी बेटी में बस 19–20 का ही फर्क लगता है। सोशल मीडिया पर आशी के साथ शुभांगी अत्रे की तस्वीरों पर ढेरों लाइक्स आ चुके हैं।

'भाबीजी घर पर हैं' से अलग हुईं शुभांगी अत्रे : बता दें, शुभांगी अत्रे 'भाबीजी घर पर हैं' सीजन 2 से अलग हो चुकी हैं और उनकी जगह शो में शिल्पा शिंदे ने वापसी की है, जो पहले भी अंगूरी भाभी के किरदार से सुर्खियों बटोर चुकी थीं। उनके शो छोड़ने के बाद ही शुभांगी अत्रे ने उनकी जगह ली थी और किरदार को बखूबी निभाया भी। इसी बीच शुभांगी अत्रे ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में शो छोड़ने पर भी बात की थी और बताया था कि करीब 1 साल से उनकी इसे लेकर मेकर्स से बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से इस पर विचार कर रही थीं, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पा रही थीं। ऐसे में उनकी बेटी आशी ने उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया ट्राय करने के लिए प्रेरित किया।

राजस्थान में युवाओं को 'बिना खर्ची और पर्ची' के मिल रहीं नौकरियां: राठौड़

जयपुर, (भाषा) राजस्थान में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य सरकार के भर्ती कैलेंडर का बचाव करते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार ने 2026 के लिए एक लाख से अधिक सरकारी पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं को ऐतिहासिक सौगात दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने यहां मीडिया से बातचीत में राज्य की भाजपा सरकार को युवा हितैषी बताते हुए कहा कि यह 44 भर्ती परीक्षाओं की स्पष्ट रूपरेखा है, जिससे युवा समय पर अपनी तैयारी कर सकेंगे। राठौड़ ने कहा, ''यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शी, समयबद्ध और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है।'' उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पांच साल में चार लाख सरकारी और छह लाख निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसके अनुसरण में पिछले दो साल में 92 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई और 1.53 लाख पदों पर प्रक्रियाधीन हैं। राठौड़ ने इसकी तुलना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से करते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में कई भर्तियां या तो संविदा वाली थीं या अदालतों में अटकी रहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले दो साल में एक भी प्रश्न पत्र लीक हुए बिना 296 परीक्षाएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस पर वर्ष 2026 में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं को ऐतिहासिक सौगात दी है।'' कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा, ''आज जो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, वे अपने कार्यकाल की सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं।'' भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार के कामों के कारण उत्साह की नयी किरण का संचार हुआ है, न केवल पारदर्शिता पूर्ण सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए भी व्यापक कार्य हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अपने आपसी फूट के संकट से ग्रस्त है और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय अनर्गल बयान दे रही है।

चुनाव से पहले केरल में होंगे चौंकाने वाले सियासी उलटफेर: वी डी सतीशन

तिरुवनंतपुरम, (भाषा) केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई दल तथा कुछ निर्दलीय नेता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में 'सियासी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं'। हाल में मीडिया की कुछ खबरों में कहा गया था कि कांग्रेस नीत यूडीएफ ने अपनी पूर्व सहयोगी और फिलहाल एलडीएफ की प्रमुख घटक केरल कांग्रेस (एम) से संपर्क साधा है। ऐसे में सतीशन का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सतीशन ने पत्रकारों से बातचीत में इन खबरों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, लेकिन कहा कि केरल कांग्रेस (एम) फिलहाल एलडीएफ के हिस्से के रूप में काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूडीएफ ऐसा कोई बयान नहीं देगा, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़े। उन्होंने कहा, ''चुनाव से पहले केरल में सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। एलडीएफ और राजग के दल तथा कुछ निर्दलीय नेता यूडीएफ के मंच पर आएंगे। अभी यह मत पूछिए कि वे कौन हैं? सही समय पर मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी।'' सतीशन ने कहा कि ऐसी चीजों का खुलासा पहले से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ दिन इंतजार करें तो उन्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि यह उलटफेर क्या है। इस बीच, केरल कांग्रेस (एम) के अध्यक्ष जोस के. मणि पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मजबूती से एलडीएफ के साथ रहेगी, लेकिन सोमवार को सत्तारूढ़ मोर्चे द्वारा आयोजित केंद्र–विरोधी सत्याग्रह में उनकी अनुपस्थिति से राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं। हालांकि, मणि ने मंगलवार को 'फेसबुक' पर पोस्ट कर दोहराया कि केरल कांग्रेस (एम) वाम मोर्चे के साथ है। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य निजी कारणों से उन्हें केरल से बाहर जाना पड़ा था, जिसके चलते वह विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर: शोभा करंदलाजे

जयपुर, (भाषा) केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम है। जयपुर के उद्योग भवन में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की राजस्थान में प्रगति की समीक्षा करते हुए करंदलाजे ने केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली और उनकी प्रगति के संबंध में दिशा–निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 10.50 लाख एमएसएमई इकाइयां को केंद्र सरकार द्वारा 29 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को प्राप्त ऋण में 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। करंदलाजे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का ऋण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, ''देशभर में 7.50 करोड़ एमएसएमई उद्यमियों का उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, और 30 करोड़ से अधिक लोगों को एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार मिला है। कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने में एमएसएमई क्षेत्र दूसरे स्थान पर है।'' करंदलाजे ने कहा, ''राजस्थान ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 1.13 लाख को टूल किट वितरित की जा चुकी है तथा एक लाख टूल किट और वितरित की जाएंगी।'' उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ मिलकर एमएसएमई क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएगी और अधिक उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों को खारिज किया

मैसूर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में मुख्यमंत्री पद पर संभावित बदलाव को लेकर मीडिया में जारी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि वह कांग्रेस आला कमान के फैसले का पालन करेंगे। हवाईअड्डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संक्षिप्त मुलाकात के बाद संवाददाताओं से मुखातिब सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राहुल से मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा, ''आज सुबह कोई चर्चा नहीं हुई और न ही शाम को कोई चर्चा निर्धारित है। वह (राहुल) तमिलनाडु के गुडालुर जा रहे हैं और दिल्ली वापसी के लिए मैसूर लौटेंगे। मैं उन्हें विदा करने जाऊंगा।'' नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से जुड़ी खबरों के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरमैया ने कहा, ''कैसी अटकलें? आप (मीडिया) ही अटकलें लगा रहे हैं। पार्टी के भीतर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यह सवाल ही बेबुनियाद है।'' मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जुड़ी अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''किस बात को लेकर भ्रम है? ये सब अखबारों और मीडिया में हो रही चर्चाएं हैं; पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं है।'' कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पिछले साल 20 नवंबर को पांच वर्ष के कार्यकाल का आधा पड़ाव पूरा करने के बाद नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। 2023 में कांग्रेस सरकार के गठन के समय सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच ''सत्ता–साझाकरण'' समझौते की खबरों के चलते नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा मिली है। विधायकों के नेतृत्व परिवर्तन की तारीख बताने से जुड़ी खबरों पर सिद्धरमैया ने कहा, ''इस मुद्दे पर या तो (उपमुख्यमंत्री) डीके शिवकुमार बोलेंगे या मैं, क्योंकि हम ही इस बारे में जानते हैं। क्या हमने बात की है? नहीं। वास्तव में, विधायक अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; यह आप (मीडिया) हैं, जो इस पर चर्चा कर रहे हैं।'' यह पूछे जाने पर कि शिवकुमार और उनके समर्थक सत्ता हस्तांतरण के वादे का जिक्र कर रहे हैं, सिद्धरमैया ने कहा, ''यह कब कहा गया था? उन्होंने कुछ नहीं कहा; आप कहानियां गढ़ रहे हैं। अंत में आला कमान जो भी फैसला करेगा, हम उसका पालन करेंगे।'' विधायकों के उनके कार्यकाल पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के मुद्दे पर सिद्धरमैया ने कहा, ''विधायकों को कोई जानकारी नहीं है। आला कमान ने उन्हें सूचित नहीं किया है। फैसला आला कमान के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि नेतृत्व संबंधी मुद्दों को स्थानीय नेताओं को सुलझाना चाहिए, सिद्धरमैया ने कहा, ''शिवकुमार और मैंने इस बारे में चर्चा की है और यहां तक कि हम एक–दूसरे के घर नाश्ते के लिए भी गए थे। हम आला कमान के फैसले का पालन करने पर सहमत हुए हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर कांग्रेस आला कमान के साथ चर्चा करने के लिए तत्काल नयी दिल्ली नहीं जाएंगे।

ईरान से व्यापार पर अमेरिका के प्रस्तावित शुल्क पर स्पष्टता का इंतजार: वाणिज्य सचिव अग्रवाल

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत ने कहा कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के कार्यकारी आदेश का इंतजार कर रही है, ताकि इसके असर का आकलन किया जा सके। ईरान को भारत का निर्यात मुख्य रूप से 'मानवीय आधार' पर दी जाने वाली जरूरी वस्तुओं का है, जिसमें प्रमुख रूप से वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। ट्रंप ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि ''तत्काल प्रभाव से'', ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ किए जाने वाले अपने सभी व्यापार पर 25 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस घोषणा के भारत पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ''ईरान के साथ हमारा व्यापार सीमित है। मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का हमारा निर्यात मानवीय प्रकृति का है। हम इस (घोषणा) को देख रहे हैं और फिलहाल विस्तृत विवरण तथा (कार्यकारी) आदेश का इंतजार कर रहे हैं।'' निर्यातकों के शीर्ष निकाय (फियो) ने कहा है कि भारतीय कंपनियां और बैंक ईरान पर 'ओएफएसी' (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) के प्रतिबंधों का पूरी तरह और स्पष्ट रूप से पालन कर रहे हैं। संगठन के अनुसार, ये इकाइयां विशेष रूप से केवल अनुमति प्राप्त मानवीय व्यापार में लगी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोजन और दवाएं शामिल हैं। इससे पहले, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा नवंबर 2018 में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारी गिरावट आई थी आंकड़ों के अनुसार, 2024–25 में ईरान के साथ भारत का कुल व्यापार 1.68 अरब डॉलर था, जिसमें 1.24 अरब डॉलर का निर्यात शामिल था। यह निर्यात मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित था। भारत के कुल 437 अरब डॉलर के वैश्विक निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी मात्र 0.28 प्रतिशत है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सेनानी तिलका मांझी

भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का माना जाता है लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780–84 में ही बिहार के संथाल परगना में तिलका मांझी की अगुवाई में शुरू हो गया था। तिलका मांझी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। 1857 की क्रांति से लगभग सौ साल पहले स्वाधीनता का बिगुल फूंकने वाले तिलका मांझी को इतिहास में खास तव्वजो नहीं दी गई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आन्दोलन में तिलका मांझी को आदिविद्रोही का दर्जा प्राप्त है, जिन्होंने ईस्ट इण्डिया कंपनी के बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीन पर कब्जे के खिलाफ पहाड़िया आदिवासियों के आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रथम प्रतिरोध के रूप में पहाड़िया आदिवासियों का यह उलगुलान राजमहल की पहाड़ियों और संथाल परगना में 1771 से लेकर 1791 तक ब्रिटिश हुकूमत, महाजन, जमींदार, जोतदार और सामंतों के विरुद्ध अनवरत चलता रहा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जंगल तराई इलाके (संथाल परगना, भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, राजमहल, खड्गपुर) में पहाड़िया आदिवासी मुख्यतः आखेटक, खाद्य (अनाज) संग्रहक, झूम खेती एवं जंगल के उत्पादों–लकड़ी, फल–फूल, पत्तों, जड़ी–बूटी पर निर्भर समुदाय थे। जंगल के इस सम्पूर्ण भू–भाग पर उनका कब्जा था और यही आदिवासियों की जीविका के साधन और जीवन जीने के संसाधन थे और मैदानी भागों के जमींदार इन पहाड़िया आदिवासी सरदारों को नियमित नजराना और व्यापारी चुंगी देते थे। बदले में आदिवासी सरदारों द्वारा सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने जमींदारों के साथ मिलकर आदिवासी क्षेत्रों की जमीनों पर कब्ज़ा कर राजस्व वसूली, भू–बंदोबस्त और शोषण का कार्य शुरू कर अपना मालिकाना हक़ जताना शुरू कर दिया था। कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में अगले दस साल के लिए जमींदारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। झूम खेती और जंगलों को काटकर स्थायी खेती करने के आदेश दिए। भू–बंदोबस्त, दिकु (जमींदार, साहूकार) और नई प्रशासनिक व्यवस्था ने इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संतुलन को गड़बड़ा दिया। 1769–70 के अकाल ने इस संकट को अधिक गहरा कर दिया। लिहाजा दोनों के बीच टकराव बढ़ने लगा था। कंपनी और उसके सहयोगियों ने सैनिक दमन तेज कर दिया और आदिवासी सरदारों को लालच दिया। दूसरी तरफ वारेन हेस्टिंग्ज़ ने 1772 में 800 सिपाहियों की एक शस्त्र सेना का गठन कप्तान रोबर्ट ब्रुक के नेतृत्व में किया। ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधिकारियों ने रोबर्ट ब्रूक के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए राजमहल, खड़गपुर और भागलपुर को मिलाकर के एक मिलिट्री कलेक्टरी नवम्बर 1773 में गठित की। ब्रूक के बाद मेजर जेम्स ब्राउनी ने भी लालच की नीति को अपनाया। लेकिन पहाड़िया आदिवासी एवं उनके छापामार संघर्ष के खिलाफ वो असफल रहे। नई नीति के तहत कंपनी अधिकारियों ने पहाड़िया सरदारों और गांव वालों को अंग्रेजी कैंपों में बुलाना, उपहार, नगदी, अनाज और सम्मान में पगड़ी पहनाना शुरू किया। साथ ही साथ गैर आदिवासियों अथवा गैर–पहाड़िया लोगों को मैदानी भागों में स्थायी रूप से बसने के लिए बाहर से बुलाया गया। कंपनी के सेवानिवृत और पूर्व नौकरशाहों को 'इनवैलिड जागीर' के नाम से ज़मीनों पर मालिकाना हक़ देना शुरू किया ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनसांख्यिकी को तब्दील किया जा सके। पहाड़िया सरदारों के उत्तराधिकारियों को कंपनी ने मान्यता देना और निर्धारित स्थानों पर हाट (साप्ताहिक बाजार) लगाने की अनुमति दी गयी। आदिवासियों से मुचलके शपथ पत्र भरवाये गए जिनमें अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादार रहने का वादा लिया गया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। नतीजतन कंपनी ने 1779 में आगस्टस क्लीवलैंड (चिलमिल साहेब) को भागलपुर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की जिम्मेदारी के साथ भेजा। क्लीवलैंड ने लालच और भय के साथ उनकी सैनिक क्षमता और युद्धकला का इस्तेमाल अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए करते हुए ''हिलरेंजर्स'' (अनियमित सेना) का गठन किया। जिसे कुछ समय बाद 'भागलपुर हिल रेंजर्स' तब्दील कर दिया गया, लेकिन 1857 के बाद इसे भंग कर दिया। इसी तरह 1782 में 'हिल असेंबली' और एक नयी प्रशासनिक इकाई ''दामिन–ए–कोह'' का गठन किया गया। आदिवासियों के आरक्षित क्षेत्रों में दिकुओं के प्रवेश, राजस्व उगाही, इनवैलिड जागीर की उपस्थिति ने तिलका मांझी एवं अन्य पहाड़िया आदिवासियों के उलगुलान की पृष्ठभूमि तैयार की। तिलका मांझी ने भागलपुर में बनचरीजोर नामक स्थान पर अंग्रेजों पर हमला करके उलगुलान की शुरुआत की। अंग्रेजी खजाने और गोदामों को लूट कर आदिवासियों में बांट दिया गया। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को राजमहल पहाड़ियों के मध्य बसे सेंगारसी/ सिंगारसी पहाड़ (संथाल परगना) नामक गांव में हुआ था, पिता सुगना मुर्मू गांव के मांझी (मुखिया) थे। संथाल परगना गजेटियर्स में जबरा/जौराह पहाड़ियों का जिक्र ही हिल रेंजर्स के सरदार, कुख्यात डकैत, गुस्सैल मांझी के रूप में जिक्र किया गया है जो बाद में तिलका मांझी नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉ. सुरेश कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक ''ट्राइबल सोसाइटी ऑफ़ इंडिया'' में जौरा/जौराह/जबरा/जौराह पहाड़िया और तिलका मांझी को एक ही व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया है। ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉ. कुमार सुरेश सिंह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनजातीय समाजों के इतिहास, समाजशास्त्र और संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया है। डॉ. कुमार सुरेश सिंह को आदिवासी इतिहास के अध्ययन के लिए जाना जाता है।

पहाड़िया में 'तिलका' का मतलब है, ऐसा व्यक्ति जो गुस्सैल हो और जिसकी आंखें लाल–लाल हों। तिलका मांझी का स्वभाव इतना गर्मजोशी भरा था कि उनका नाम ही तिलका पड़ गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे थे। 'जबरा पहाड़िया' आगे चलकर गांव का प्रधान बन गया। उनके समुदाय में ग्राम प्रधान को 'मांझी' बुलाते थे। इस तरह 'जबरा पहाड़िया' का नाम तिलका मांझी बन गया। धीरेन्द्रनाथ बास्की ने बंगाली भाषा में लिखित अपने 'संथाल गणसंग्रामर' इतिहास 1781–1785 के संथाल विद्रोह और तिलका मुर्मू द्वारा कलेक्टर की हत्या और तिलका का संथाल आदिवासी के रूप में जिक्र किया है। राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास ''हूल पहाड़िया'' में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया है। उसी तरह महाश्वेता देवी का उपन्यास 'शाल गिरर की पुकार' में तिलका मांझी/ जबरा पहाड़िया/ जौराह पहाड़िया के जीवन और उलगुलान के बारे में लिखा है। राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने भी अपनी पुस्तक में तिलकामांझी के किरदार के बखूबी लिखा है। वहीं हाल में वाणी प्रकाशन से घनश्याम द्वारा लिखी गई पुस्तक ''आदिविद्रोही तिलका मांझी''का प्रकाशन हुआ है। यह पुस्तक तिलका मांझी के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। तिलकामांझी ने अंग्रेजों के अत्याचार को देखा था, आदिवासियों की जमीनों पर दिकुओं का कब्जा था। दिकुओं और पहाड़िया आदिवासियों के मध्य अक्सर इसी को लेकर संघर्ष होता रहता था। जमींदार तबका अक्सर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ होता था। तिलका मांझी के नेतृत्व में चले इस उलगुलान का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की ज़मीनों पर राजस्व वसूली, आदिवासियों की जमीनों पर गैर आदिवासियों को मालिकाना हक़, फूट डालो–राज करो की नीति और सैनिक कारवाईयों का विरोध करना तथा दिकुओं की सत्ता को समाप्त करना था।'झारखण्ड इनसाइक्लोपीडिया: हुलगुलानों की प्रतिध्वनि' में सुधीर पॉल और रणेन्द्र लिखते हैं कि गंगा–ब्राह्मी के तराई वाले क्षेत्र– मुंगेर, भागलपुर और संथाल परगना में कई लड़ाइयां हुई। जिसमें एक तरफ भागलपुर कलेक्टर आगस्टस क्लीवलैंड और सेनापति जनरल सर आयर कूट और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार किए हुए सरदारों का गठबंधन था, तो वहीं दूसरी तरफ तिलका मांझी उर्फ जबरा/ जौराह पहाड़िया। तिलका मांझी ने 1780–85 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर लगातार हमले किये। इसके लिए आदिवासियों और अन्य लोगों को एकजुट करना शुरू किया। शाल के पेड़ की छाल में गांठ बांध कर गांव–गांव आदिवासियों को एकजुट होने का निमंत्रण भेजा गया। मारगो दर्रा, तेलिया गढ़ी और कहलगांव में अंग्रेजी खजाने को लूटकर आदिवासियों में बांट दिया। अंग्रेजी हुकूमत, सामंतों, जमींदार, साहूकार, महाजन, दिकुओं पर आदिवासियों के हमले जारी रहे। 1780 में पहाड़िया सरदारों– रमना अहाड़ी, अमड़ापाड़ा प्रखंड (पाकुड़/ संथाल परगना) के आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजहर के साथ मिलकर अंग्रेजों से रामगढ़ (हजारीबाग) कैंप छीन लिया।आदिवासियों के इन हमलों, आवागमन को रोक देने की कार्रवाई के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत और उसके सान्निध्य प्राप्त जमींदारों ने भागलपुर हिल रेंजर्स के साथ सैनिक दमन तेज कर दिया, जिसमें आदिवासी गांवों को जला देना, हत्या करना, गिरफ्तारी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसी कार्यवाहियां की गई। 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने भागलपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिल रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला किया। जहर लगे तीरों से तत्कालीन भागलपुर कलेक्टर आगस्टस क्लीवलैंड घायल हो गया। कलेक्टर के हमले के बाद इलाज के लिए इंग्लैंड लौटते वक़्त एटलस इंडिआना नामक जहाज पर कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर ही इनकी मौत हो गई और बाद में इन्हें पार्क स्ट्रीट कोलकाता सिमेट्री में दफना दिया गया। क्लीवलैंड की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया। तिलका और उसके साथियों को पकड़ने के लिए खोजी ऑपरेशन चलाये जाने लगे। आदिवासी गांवों को आग लगा दी गई। आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन तिलका किसी तरह बचकर पहाड़ पर चला गया। कलेक्टर की मौत ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिला दिया था। यह घटना कंपनी के लिए गहरा सदमा थी। 1784–1785 में आदिवासियों पर ब्रिटिश फ़ौज ने हमला किया। फूट डालो–राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने आदिवासियों को लालच देना और भड़काना शुरू कर दिया अंततः किसी ने मुखबिरी की। अंग्रेजी सेनापति जनरल सर आयर कूट ने रात के अंधेरे में आदिवासियों के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन तिलका ने भाग कर सुल्तानगंज की पहाड़ियों में शरण ली।अंग्रेजी फौज ने पूरे पहाड़ की घेराबंदी करके रसद आपूर्ति एवं अन्य दैनिक उपयोग की चीजों पर रोक लगा दी। कई महीनों की घेराबंदी के बाद आदिवासी लड़ाकों को पहाड़ी ठिकानों से निकलकर बाहर मैदानों में आना पड़ा। जहां दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष के बाद अंततः तिलका मांझी को गिरफ्तार करके घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया। जहां एक चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें 1785 में फांसी पर लटका दिया गया। तिलकामांझी का नारा था कि – पृथ्वी हमारी है। तिलकामांझी ने कहा था यह धरती सिंगबोंगा (सूर्य) की देन है। मतलब प्रकृति की देन है । प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्ति या राज्य का कब्जा नहीं हो सकता हो सकता। आजीवन वे इसके लिए संघर्षरत रहे।आज भी जमीन बचाने की जंग में जनजातीय समुदाय आगे है। भागलपुर में जिस क्षेत्र में तिलकामांझी को फांसी दी गई, वह इलाका तिलकामांझी मुहल्ले के रूप में आबाद है। यहां तिलकामांझी हटिया भी है। ये कब अस्तित्व में आए इसका पता कई पीढ़ियों को नहीं है। तिलकामांझी चौक पर प्रमंडलीयआयुक्त अरुण पाठक और जिला पदाधिकारी मनोज कुमार मंडल के कार्यकाल में पत्रकार बंकिम चंद्र बनर्जी के प्रयासों से तिलकामांझी चौकपर तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गयी। बाद में 1992 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नामाकरण तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर उसी महान सेनानी को सम्मान दिया गया। तिलकामांझी की मौत के बाद अंग्रेजी हुकूमत और उसके दिकु सहयोगियों ने उलगुलान को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कई तरह के उपाय किये। लेकिन आदिवासियों ने तिलका की मशाल को जलाए रखा। 1788 में बीरभूम जिले में पहाड़िया आदिवासियों ने ब्रिटिश कचहरी और कोठियों पर, महाजन, व्यापारी और जमींदारों के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। इसी तरह जनवरी 1789 के पहले सप्ताह में 500 आदिवासियों ने बांकुरा जिले के जमींदार के बाजार और अनाज गोदामों पर हमला किया। जून 1789 में बांकुरा जिले के आलम बाजार पर आदिवासियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1789 में विष्णुपुर के राजनगर कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया। धीरे धीरे पूरा वीरभूम जिला आदिवासियों के कब्जे में आ गया। जिसके कारण अंग्रेजों ने वीरभूम और बांकुरा क्षेत्र के लिए अलग अलग कलेक्टर नियुक्त कर दिये गए। सांगठनिक कमजोरी, आंतरिक मतभेद और आधुनिक हथियारों के मुक़ाबले परंपरागत हथियारों कि कमियों के कारण 1791 तक पहाड़िया उलगुलान ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात उसी क्षेत्र के आसपास तिलका मांझी की प्रेरणा से भूमिज विद्रोह (1798 मानभूम), चेर (1810 पलामू), मुंडा (1819 –20), कोल (1833), भूमजी (1834), संथाल (1855), मुंडा (1895–1900) इत्यादि के रूप में उलगुलान की मशाल को आदिवासियों ने जलाए रखा। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष 1947 तक जारी रहा। लेकिन दिकुओं के खिलाफ आज भी जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई आदिवासी समाज लड़ रहा है। तिलका मांझी आज भी पहाड़िया आदिवासियों की कहानियों, स्मृतियों और गीतों में जिन्दा है।

क्या पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करने से अमेरिका को मिलेगा लाभ?

पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली एक रणनीतिक तकनीकी पहल है जो सिलिकॉन–आधारित सप्लाई चेन को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह एआई, सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निर्भरता कम करने का प्रयास करती है। यह नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय पहल क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा संसाधनों, चिप निर्माण, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाती है। इसलिए अमेरिकी विदेश विभाग इसे "पॉजिटिव–सम" साझेदारी मानता है, जो चीन जैसी निर्भरताओं से बचाव करती है। इससे विश्वसनीय देशों में नवाचार और निवेश बढ़ता है।इस प्रकार पैक्स सिलिका का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम करना और विश्वसनीय देशों के बीच सुरक्षित तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। चूंकि भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है, इसलिए भारत को हाल ही में इसमें पूर्ण सदस्यता का न्योता मिला है, जो ग्लोबल चिप हब बनने का अवसर देगा। इससे जहां अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी कंपनियों से भारी निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार सृजन होगा। वहीं रक्षा, अंतरिक्ष और सैन्य सुरक्षा में भी मजबूती मिलेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि यह वैश्विक पहल महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा स्रोतों, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण, एआई अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में दबावपूर्ण निर्भरताओं को घटाती है। उच्च–तकनीकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक सह–निवेश को बढ़ावा देकर नवाचार को प्रोत्साहित करती है। संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को चिंताजनक देशों से बचाने का लक्ष्य रखती है। जहां तक इसकी संरचना की बात है तो अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य के रूप में नेतृत्व करता है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले देश शामिल हैं। यह गठबंधन–आधारित मॉडल पर काम करती है, जो साझा निवेश और सहयोग पर जोर देती है। भारत को हाल ही में पूर्ण सदस्यता का निमंत्रण मिला है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को इसमें शामिल करने की घोषणा की। जबकि इससे पहले टैरिफ विवाद से भारत बाहर था, लेकिन अब यह साझेदारी भारत–अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई देगी। पैक्स सिलिका में अमेरिका नेतृत्व करता है और इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। यह पहल विश्वसनीय साझेदार देशों को जोड़ती है ताकि सिलिकॉन सप्लाई चेन मजबूत हो। इसके मुख्य सदस्य देश निम्नलिखित हैंः– संस्थापक सदस्यः अमेरिका (नेतृत्वकर्ता), जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान। अन्य प्रमुख सदस्यः नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। मसलन, ये देश उच्च–तकनीकी विनिर्माण और AI क्षेत्रों में मजबूत क्षमता रखते हैं। इससे भारत को सेमीकंडक्टर और AI सप्लाई चेन में प्रमुख स्थान मिलेगा। भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने से चीन पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने से चीन पर मुख्य रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह पहल विशेषकर सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन में उसके एकाधिकार को चुनौती देगी। रूस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, लेकिन सीधा उल्लेख कम है। यह वैश्विक तकनीकी निर्भरता को पुनर्गठित करेगा। इसका चीन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चीन वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा स्रोतों, चिप निर्माण और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर हावी है। लिहाजा पैक्स सिलिका के माध्यम से भारत का प्रवेश उसके प्रभुत्व को कम करेगा, दबावयुक्त निर्भरता घटाएगा और वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाएगा। इससे चीन के निर्यात बाजार और तकनीकी वर्चस्व पर दबाव बढ़ेगा। जहां तक रूस पर प्रभाव की बात है तो रूस पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ट्रंप प्रशासन के रूसी तेल खरीद पर 500% टैरिफ जैसे कदमों से व्यापक आर्थिक दबाव जुड़ सकता है। दरअसल पैक्स सिलिका ऊर्जा स्रोतों की सुरक्षित चेन पर फोकस करता है, जो रूस के पारंपरिक ऊर्जा निर्यात को अप्रत्यक्ष चुनौती दे सकता है। इसका सामरिक निहितार्थ यह होगा कि भारत के बढ़े कदम से अमेरिका–भारत साझेदारी मजबूत होगी।इसको मजबूत कर भू–राजनीतिक संतुलन बदलेगा, जहां चीन–रूस गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है। जबकि भारत को निवेश और तकनीक मिलने से उसकी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने से चीन पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने से चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा क्योंकि नई पहल मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में उसके वर्तमान प्रभुत्व को कम करके बढ़ेगा। यह वैकल्पिक उत्पादन केंद्र स्थापित कर चीन के निर्यात बाजार को सीधे चुनौती देगा। रणनीतिक रूप से यह अमेरिका–नीत गठबंधन को मजबूत करेगा। जहां तक सप्लाई चेन पर प्रभाव की बात है तो चीन सिलिकॉन, चिप निर्माण और AI हार्डवेयर में 70–90% वैश्विक आपूर्ति नियंत्रित करता है। लिहाजा इसमें भारत का प्रवेश निवेश आकर्षित कर उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, जिससे चीन के बाजार हिस्से में 10–20% गिरावट आ सकती है। इससे उसके निर्यात राजस्व में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इससे निर्यात और बाजार हानि भी होगी क्योंकि भारत जैसे नए केंद्रों से जापान, कोरिया और यूरोपीय कंपनियां खरीदारी स्थानांतरित करेंगी। चीन के सस्ते उत्पादों पर निर्भरता घटेगी, जिससे उसके व्यापार अधिशेष पर दबाव पड़ेगा। लंबे समय में AI और टेक निर्यात 15–25% कम हो सकते हैं। जहां तक भू–आर्थिक परिणाम की बात है तो भारत का यह कदम चीन को तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए मजबूर करेगा, लेकिन तत्काल पूंजी और बाजार हानि से उसकी विकास दर 0.5–1% धीमी हो सकती है। भारत–अमेरिका साझेदारी से वैश्विक टेक व्यापार का पुनर्वितरण होगा। इस प्रकार देखा जाए तो भारत को अपने पाले में मिलाने के लिए और रूस–चीन से उसकी रणनीतिक दूरी बढ़ाने के लिए दुनिया का थानेदार अमेरिका बेकरार है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष भारत जिधर होगा उस वैश्विक गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय वजन स्वतः बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए कि भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला गणतांत्रिक देश है। यहां के लोगों में बल और बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी है। आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ब्रेक के बाद एक से बढ़कर एक वैश्विक गुटीय ऑफर दे रहा है। यह बात अलग है कि रूस से भारत के घनिष्ट रिश्ते में खटास पैदा करने के लिए वह टैरिफ इजाफे का भी दांव चल चुका है और आगे ज्यादा करने की धमकी भी दे रहा है। वहीं द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को भी बेवजह लंबा खींच रहा है। ऐसे में अमेरिका अब भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं हो सकता है। लेकिन रूसी–चीनी दोस्ती के दृष्टिगत अमेरिका से खुलेआम शत्रुता भी नहीं की जा सकती। इसलिए चीन की तरह ही अमेरिका से भी शो शो का रिश्ता रखना लाजिमी है। अनुभव बताता है कि अमेरिका भारत से अपनी मनवाने पर तुला हुआ है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण पर अडिग है जिससे अमेरिका की हर कोशिश कमतर प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए कि भारत अपने भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय मंच मित्र रूस को न तो छोड़ना चाहता है और न ही अपने रणनीतिक दुश्मन चीन–पाकिस्तान से बेवजह पंगा लेना चाहता है, क्योंकि भारत निज विकास के द्वारा अपनी जनता के जीवन स्तर में बढ़ोतरी को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि अब अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका समूह में शामिल करने का लॉलीपॉप थमाया है, ताकि भारत को पटाकर रणनीतिक लाभ हासिल किया जा सके।

कमलेश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

अमेरिका को निर्यात दिसंबर में 1.83 प्रतिशत घटकर 6.88 अरब डॉलर पर

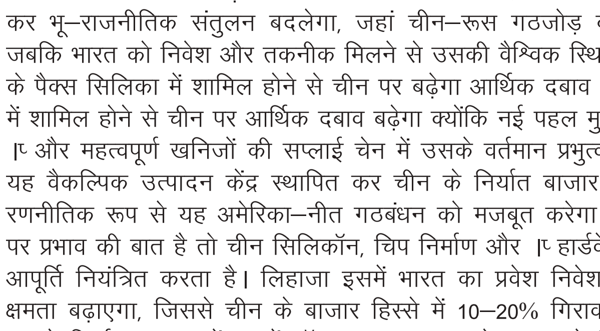

नयी दिल्ली, (भाषा) ऊंचे शुल्क के कारण भारत का अमेरिका को वस्तु निर्यात दिसंबर महीने में 1.83 प्रतिशत घटकर 6.88 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाए जाने के बाद पिछले वर्ष सितंबर और अक्टूबर में भी निर्यात घटा था। हालांकि, नवंबर महीने में इसमें 22.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।अमेरिका को निर्यात दिसंबर 2024 में 7.01 अरब डॉलर रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने अमेरिका से आयात 7.57 प्रतिशत बढ़कर 4.03 अरब डॉलर हो गया। इसके साथ चालू वित्त वर्ष में अप्रैल–दिसंबर अवधि के दौरान देश का अमेरिका को निर्यात 9.75 प्रतिशत बढ़कर 65.87 अरब डॉलर जबकि आयात 12.85 प्रतिशत बढ़कर 39.43 अरब डॉलर रहा। अमेरिका ने 27 अगस्त से अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिया है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

चांदी 3,000 रुपये चढ़कर 2.89 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर, सोना ने भी बनाया रिकॉर्ड

नयी दिल्ली, (भाषा) चांदी की कीमत राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को 3,000 रुपये की तेजी के साथ 2,89,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं स्टॉकिस्टों और आभूषण कारोबारियों की लगातार खरीदारी के बीच सोना 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। लगातार पांचवें दिन बढ़त बनाए रखते हुए, चांदी की कीमत 3,000 रुपये यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 2,89,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों को मिलाकर) के नए शिखर पर पहुंच गई। यह बुधवार को 2,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस नई बढ़त के साथ, चांदी पिछले पांच सत्रों में लगभग 16 प्रतिशत यानी 45,500 रुपये उछली है। इसकी कीमत आठ जनवरी को 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी। चांदी लगातार दूसरे साल सोने से आगे रही है, जिसने अब तक 21 प्रतिशत का लाभ दिया है और 31 दिसंबर, 2025 को रिकॉर्ड किए गए 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 50,000 रुपये बढ़े हैं। इसके साथ, सोने की कीमतों में लगातार पांचवें दिन बढ़त जारी रही। बृहस्पतिवार को यह 800 रुपये बढ़कर 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत 9,600 रुपये यानी लगभग सात प्रतिशत बढ़ चुकी है। कारोबारियों ने घरेलू सर्राफा कीमतों में लगातार तेजी का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुस्त रुख के बावजूद आभूषण विक्रेताओं, स्टॉकिस्ट और खुदरा उपभोक्ताओं की लगातार खरीदारी को बताया। पीएल वेल्थ मैनेजमेंट के उत्पाद और फैमिली ऑफिस के प्रमुख, राजकुमार सुब्रमण्यम ने कहा कि मौजूदा चक्र में चांदी सबसे आकर्षक रणनीतिक धातु में से एक के रूप में उभर रही है, जो निवेश मांग और औद्योगिक रूपांतरण के मिलन बिंदु पर है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आने के बाद हल्का तकनीकी सुधार देखा गया। बुधवार को 93.52 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड छूने के बाद चांदी 1.98 डॉलर यानी 2.13 प्रतिशत गिरकर 91.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। विदेशी व्यापार में हाजिर सोना भी 12.22 डॉलर यानी 0.26 प्रतिशत घटकर 4,614.45 डॉलर प्रति औंस पर रहा। पिछले सत्र में इसने 4,643.06 डॉलर प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बनाया था।

दिसंबर में चीन को भारत का निर्यात 67.35 प्रतिशत बढ़ाः वाणिज्य मंत्रालय आंकड़े

नयी दिल्ली, (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों जैसी विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में उछाल से पिछले साल दिसंबर में चीन को होने वाला भारतीय निर्यात 67.35 प्रतिशत बढ़कर 2.04 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली। निर्यात में यह तेजी मुख्य रूप से तेल खली, समुद्री उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और मसालों जैसे उत्पादों के कारण रही। आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने के दौरान चीन से आयात भी 20 प्रतिशत बढ़कर 11.7 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–दिसंबर अवधि के दौरान चीन को होने वाला निर्यात 36.7 प्रतिशत बढ़कर 14.24 अरब डॉलर रहा, जबकि पहले नौ महीनों के दौरान आयात 13.46 प्रतिशत बढ़कर 95.95 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान व्यापार घाटा 81.71 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह एक स्वागत योग्य वृद्धि है।" इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाली मुख्य वस्तुओं में 'पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड' (पीसीबी), 'फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल' और टेलीफोनी के लिए अन्य विद्युत उपकरण शामिल रहे। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि और समुद्री उत्पादों में सूखी मिर्च, ब्लैक टाइगर झींगा, मूंग, वनमेई झींगा और तेल खल अवशेष शामिल हैं। इसी तरह, एल्युमीनियम और परिष्कृत तांबा सिल्लियों ने भी निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

एनएसई की निपटान अर्जी पर सेबी सैद्धांतिक रूप से सहमतः चेयरमैन

मुंबई, (भाषा) बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि सेबा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दायर निपटान अर्जी पर 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति दे दी है। यह कदम देश के सबसे बड़े शेयर बाजार एनएसई के विलंबित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का रास्ता साफ कर सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रमुख ने बताया कि सरकार ने बड़े मूल्यांकन वाली कंपनियों को आईपीओ में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उन्होंने गैर–सूचीबद्ध बाजार में एनएसई के शेयरों को लेकर बढ़ती दिलचस्पी पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यह मामला कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दायरे में आता है। सेबी प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनएसई की तरफ से दायर निपटान अर्जी सेबी की विभिन्न समितियों के समक्ष प्रक्रिया से गुजर रही है लेकिन नियामक सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत है। को–लोकेशन मामले में चुनिंदा ब्रोकरों को कथित तौर पर अनुचित बाजार पहुंच दिए जाने के आरोपों के कारण एनएसई का आईपीओ प्रस्ताव 2016 से ही अटका हुआ है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एनएसई ने पिछले साल 1,388 करोड़ रुपये का भुगतान कर यह मामला निपटाने का प्रस्ताव सेबी के समक्ष रखा था। सेबी से मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद एनएसई आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा। एनएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि निपटान पर सेबी की सैद्धांतिक सहमति एक 'अच्छी खबर' है, लेकिन आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ही निर्गम का मसौदा दस्तावेज दाखिल करने की तैयारी शुरू की जाएगी। चौहान ने अनुमान जताया कि एनओसी मिलने के सात–आठ महीने बाद एनएसई का आईपीओ बाजार में आ सकता है।

डाक विभाग ने ओएनडीसी के लिए लॉजिस्टिक प्रदाता के रूप में पहली खेप की सफलतापूर्वक डिलीवरी की

नयी दिल्ली, (भाषा) डाक विभाग ने 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' मंच पर बुक किए गए ऑर्डर के लिए लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में काम करना शुरू कर दिया है और अपनी पहली खेप (पार्सल) का सफलतापूर्वक डिलीवरी दी। इंडिया पोस्ट नाम से सेवाएं संचालित करने वाले डाक विभाग को ओएनडीसी पर पहला ऑर्डर 13 जनवरी, 2026 को प्राप्त हुआ था। यह ऑर्डर 'उद्यमवेल' द्वारा बुक किया गया था, जो ओएनडीसी–संबद्ध एक ऐसी पहल है, जिसका मुख्य ध्यान शिल्पकारों, किसानों और अन्य ग्रामीण उद्यमियों को व्यापक सेवाएं प्रदान कर भारतीय उद्यमियों को सहायता देना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए 13 जनवरी, 2026 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक बुक कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

Five Point Five opens 2026 with its annual Doha pop-up – 'The Doha Chapter'

New Delhi, Focus NEws: Five Point Five begins 2026 by completing three years of the brand and opening the year with its annual international pop-up in Doha, titled 'The Doha Chapter.' Held from 9-11 January 2026, this marked the label's fourth showcase in Doha, strengthening its long-standing relationship with its growing community in Qatar. Conceived as an intimate, private showcase, 'The Doha Chapter' was curated exclusively for the Five Point Five circle the brand has built in Qatar over the years. The edit stayed true to the label's philosophy of thoughtful curation and craft-led storytelling, while introducing a distinctive new narrative. The highlight of the showcase was a limited-edition capsule that brought together the textile legacies of Benaras and Gujarat. Crafted on a base of soft silk, the fabric is first woven in Benaras and then sent to Gujarat, where it is adorned with traditional hand-dyed Kutch Bandhej and Ajrakh hand-block printing. The result is a seamless blend of crafts from two distinct regions, creating saris that are deeply rooted yet refreshingly contemporary.

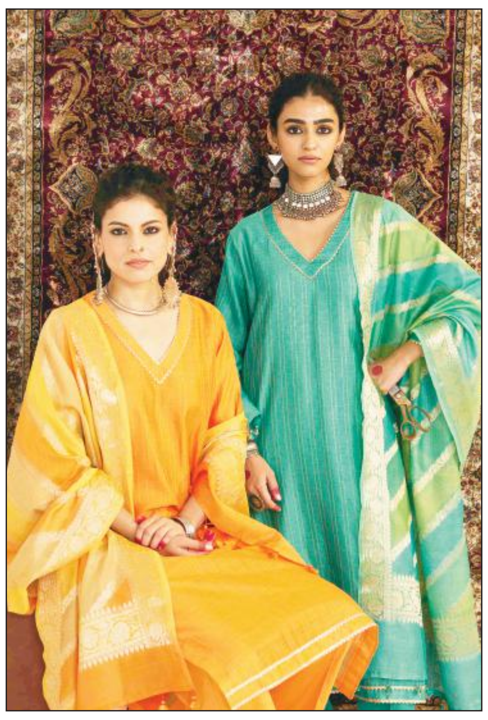

Alongside its sari offerings, Five Point Five also presented its recently diversified product range, including suit sets and a curated selection of suit fabrics, extending the brand's textile language while remaining aligned with its core aesthetic.

Speaking about the Doha showcase, Usha Ravishankar, a supporter of Five Point Five in Doha and former broadcast journalist with Doordarshan shared, "I am truly enchanted by the exquisite display of weaves; the collection was nothing short of mesmerizing - a splendid tapestry of artistry, tradition, and innovation woven seamlessly into each piece. It fills me with immense pride to see how passionately the brand engages with weavers and uplifts communities from the grassroots."

Reflecting on the brand's journey and its fourth showcase in Doha, founders Radhika Jain and Nitin Singla added, "Completing three years of Five Point Five and beginning 2026 with our fourth showcase in Doha feels deeply meaningful. 'The Doha Chapter' is a reflection of our belief in thoughtful curation, respectful craft collaborations, and the quiet power of building a community that values Indian textiles beyond borders." With 'The Doha Chapter', Five Point Five not only marked a milestone year while reaffirming its commitment to community-driven showcases, honouring Indian crafts, and presenting them within a global cultural context.

Delegation of Transport Associations calls on Chief Secretary, Ladakh

Leh, Focus News: A combined delegation of the All Kargil Transport Association (AKTA) and the All Leh Transport Association (ALTA), led by their presidents, Adv. Riyaz Ahmed and Dorjey Angchok, with their executive members, today called on the Chief Secretary, UT Ladakh, Shri Ashish Kundra, at the UT Secretariat in Leh. During the meeting, the delegation welcomed the Chief Secretary and apprised him of various issues and concerns being faced by transporters across Ladakh. The members raised key matters related to the implementation of Vehicle Location Tracking Devices (VLTD), difficulties being faced with authorised vendors, and the need to ensure smooth and transparent procedures in this regard. The delegation also highlighted problems related to the fitness certification of vehicles, particularly in remote areas where access to testing facilities remains limited. They further brought to the notice of the Chief Secretary the challenges faced by transport operators in obtaining and renewing inter-state permits through the Regional Transport Office (RTO). The Chief Secretary gave a patient hearing to the delegation and assured them that their genuine issues would be examined, directing the concerned departments to take appropriate steps for their resolution.

Pratibimb brings God's Lioness to Bengaluru after a successful Delhi, Gurugram run

Bengaluru, Focus News: Pratibimb Theatre Company arrives in Bengaluru this January with its latest production, God's Lioness, following a successful run in Delhi and Gurugram. The 80-minute production reframes the Mahabharata through a contemporary feminist and metaphysical lens, centring Draupadi's voice in a journey of silence, awakening, and choice.

Bengaluru Tour Dates

23 Jan 2026: Ranga Shankara, Bengaluru

24 Jan 2026: Jagriti Theatre, Bengaluru

29 Jan 2026: MAHE, Bengaluru

Tickets and Information

About the Production : God's Lioness places Draupadi at the centre, charting her journey through Expose, Agency, and Choice. In this staging, characters become metaphors for existential forces: Draupadi as womanhood, Kunti as society, Krishna as the divine or the universe, and the Pandavas, with Karna, as the male experience. The play blends traditional performance vocabularies with contemporary storytelling, using puppets and masks not just as spectacle but as living metaphors for agency, control, and inner truth. Director Prof. Satyabrata Rout describes the work as an inward, metaphysical inquiry in which Draupadi's long-held silence transforms into a fierce reclamation of dignity and self-determination.

For tickets and show details, please refer to –

Ranga Shankara https://in.bookmyshow.com/plays/gods-lioness/ET00477694

Jagriti Theatre https://in.bookmyshow.com/plays/god-s-lioness/ET00479364

Key Credits Playwright: Mrinal Mathur, Scenography and Direction: Prof. Satyabrata Rout

Lighting Design: Raghav Prakash Mishra, Music and Vocals: Vipin Kumar Varman, Narendra Kumar

Costume: Vidushi Sharma

Stage Manager: Susheel Kant Mishra

Production Management: Harsh Raj, Charvi Gupta

Publicity: Shubhajeet Dasgupta

Cast and Ensemble

Keshav: Suman Saha

Draupadi: Richa Srivastava

Kunti: Priyanka Sharma

Karna: Akshay Singh Thakur

The Pandavas: Puppets operated by the actors

Produced by

Pratibimb Theatre Company.

About Pratibimb Theatre Company: With roots that go back nearly five decades, Pratibimb has been revived with a clear artistic mission: to reimagine stories and myths that have become conventionally accepted, and to bridge ancient mythology with contemporary feminist discourse, creating theatre that is both thought-provoking and visually arresting. Richa Srivastava is the managing trustee of Pratibimb Theatre Company, a collective founded by her parents in Uttar Pradesh in the 1980s. Over the years, the company staged powerful works by masters like Badal Sarkar, Vijay Tendulkar, and Girish Karnad, always with one belief at its core: theatre as a reflection of life.

Experts Call for AI-Enabled Farm-Gate Quality and Traceability to Strengthen India's Medicinal Plant Supply Chain

New Delhi, Focus News: Experts across the Ministry of Ayush institutions including National Medicinal Plant Board (NMPB) has called for Artificial intelligence (AI) and related technologies to monitor, verify, and document the quality and journey of medicinal plants right from the farm (the "farm-gate") through the entire supply chain, in a two-day National Seminar on "Design and Development of Tools for Quality Assessment of Medicinal Plants at Farm Gates". The seminar held on 8–9 January 2026 at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, brought national focus to India's medicinal plant sector—assured quality, traceability, and standardisation of raw materials at the point of origin. The seminar convened policymakers, scientists, technologists, industry leaders, and researchers to deliberate on strengthening farm-gate quality systems as a foundation for the sustainable growth and global competitiveness of India's Ayush and medicinal plant ecosystem. The seminar was inaugurated with keynote addresses by Prof. Dr. Mahesh Kumar Dadhich, Chief Executive Officer, NMPB, and Prof. Dr. Tanuja Nesari, Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA). Their addresses set the national policy and scientific context for quality-driven growth, emphasising the need to integrate innovation, regulation, and traditional knowledge to build global confidence in Indian medicinal plant raw materials. Technical sessions on Day One examined the entire medicinal plant value chain—from sustainable cultivation and regenerative agriculture to AI-enabled quality assessment, digital traceability, and supply-chain integration. Experts from ICAR–Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research (DMAPR), IIT Delhi, the World Health Organization (WHO), the Ministry of Ayush , Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), Himalaya Wellness, and Herbalscape Crops shared evidence-based insights and field experiences.

The discussions highlighted that India is both technically and institutionally prepared to adopt AI-based diagnostics, digital phenotyping, and integrated quality frameworks, reinforcing the credibility of Indian medicinal plant raw materials in domestic as well as international markets. Day Two was dedicated to roadmap building through two structured expert brainstorming sessions on Integration of Artificial Intelligence in the Indian Medicinal Plant Industry, and use of Blockchain Technology for Supply-Chain Transparency and Traceability. The sessions resulted in a strong consensus that digital tools at the farm gate—such as portable quality-testing devices, AI-enabled decision-support systems, and blockchain-based traceability platforms—are no longer optional but essential to ensure authenticity, safety, and global competitiveness of Indian herbal raw materials. The seminar delivered clear and actionable outcomes aligned with the objectives of NMPB and the Ministry of Ayush. It enabled rare national-level convergence among policy institutions, scientific bodies, industry stakeholders, and global health organisations, fostering integrated solutions rather than fragmented interventions. Participants unanimously underscored that quality must be built at the point of origin, directly supporting NMPB's mandate to empower primary producers and collectors. The deliberations validated the practical deployment of AI and digital tools to reduce adulteration, variability, and farmer losses, while also establishing the critical role of blockchain-enabled end-to-end traceability for exports and pharmacopoeial compliance. The seminar also highlighted the integration of traditional knowledge systems such as Vriksha Ayurveda with modern quality-control frameworks, demonstrating how India's heritage can be scientifically validated and digitised to strengthen global acceptance. Strong emphasis was placed on capacity building, with participants gaining exposure to advanced tools, standards, and evolving policy directions.

The seminar laid a robust foundation for developing a national framework for AI-enabled, traceable, and standardised medicinal plant supply chains. The outcomes directly support the national priorities of Atmanirbhar Bharat and Make in India, while reinforcing India's leadership in the global Ayush sector The deliberations strongly underscored the need for continued and expanded support for pilot projects, technology deployment, and farmer-level capacity building under NMPB-supported initiatives, positioning farm-gate quality as a cornerstone of India's medicinal plant economy.

APEDA Inaugurates Regional Office in Raipur to Boost Agri and Processed Food Exports from Chhattisgarh

New Delhi, Focus News: In a significant step towards positioning Chhattisgarh as a major hub for agricultural and processed food exports, the Regional Office of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) was inaugurated at Raipur during the 2nd India International Rice Summit held in Chhattisgarh. The inauguration was attended by Minister of Health and Family Welfare and Minister of Medical Education, Government of Chhattisgarh, Shri Shyam Bihari Jaiswal, along with other dignitaries. Chhattisgarh, with its rich and diverse agri-ecosystem, offers significant export potential across a wide range of products. These include premium non-basmati rice varieties and Geographical Indication (GI)-tagged products such as Jeeraphool Rice and Nagri Dubraj Rice. The State also produces a variety of fruits and vegetables including guava, banana, dragon fruit, jackfruit, custard apple, tomato and cucumber, along with important minor forest produce such as mahua, tamarind, herbal and medicinal plants, providing strong opportunities to expand its presence in global markets. The establishment of the APEDA Regional Office in Raipur marks an important milestone for Chhattisgarh's agrarian economy. The new office will facilitate farmers, producer groups, cooperatives and exporters by providing services such as export registration, advisory support, market intelligence, certification assistance, export facilitation, infrastructure development and market linkage support. Recently, the APEDA Regional Office in Raipur also facilitated the export of fortified rice kernels from Chhattisgarh to Costa Rica and Papua New Guinea. Addressing the occasion, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai stated that the opening of the APEDA Regional Office in Raipur is a mission to integrate Chhattisgarh's farmers with the global economy.

EU leaders Antonio Costa, Ursula von der Leyen to visit India from Jan 25–27; attend Republic Day as Chief Guests

The President of the European Council, Antonio Luis Santos da Costa, and the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, will visit India from 25-27 January 2026, according to an official statement by the Ministry of External Affairs (MEA). Prime Minister Narendra Modi has extended an invitation to EU leaders to attend the 77th Republic Day celebrations in New Delhi as chief guests, the ministry said. During the visit, the leaders will also co-chair the 16th India-EU Summit on 27 January 2026, as India and the European Union move forward with talks on a free trade agreement. The previous India-EU Summit was held virtually on 15 July 2020. This high-profile visit follows closely on the heels of German Chancellor Friedrich Merz's trip to India, which focused on strengthening economic and security cooperation between India and the European Union's largest economy. Merz visited India on 12 January 2026.

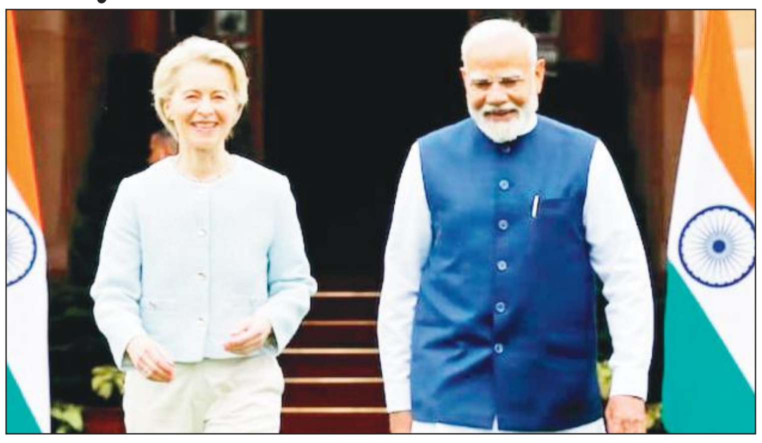

Plans for their visit : During the visit, President Costa and President von der Leyen will meet the Indian President Droupadi Murmu, and hold "restricted and delegation-level talks" with Prime Minister Modi. An India-EU Business Forum is also expected to be organised on the sidelines of the India-EU Summit, the official MEA release noted. India and the European Union have been strategic partners since 2004, the ministry said, noting that bilateral ties between India and the EU have strengthened over the years and deepened across a wide range of areas, particularly following the historic visit of the European Commission to India in February 2025. "Participation of EU leaders as Chief Guests at the 77th Republic Day and the 16th India-EU Summit will further deepen the India-EU Strategic Partnership and advance collaboration in priority areas of mutual interest," MEA said in its announcement dated 15 January.

India-EU FTA: On 9 January 2026, India and the European Union (EU) held talks in Brussels on the proposed FTA, reaffirming their commitment to a rules-based trading framework and a modern economic partnership that protects the interests of farmers and MSMEs. After a gap of more than nine years, India and the EU bloc resumed negotiations in June 2022 on a comprehensive FTA, an investment protection agreement and a pact on geographical indications.

From Rani Mukerji, Sheena Chohan, to Sobhita Dhulipala, to Huma Qureshi, Meet Actresses Who Are All Set To Rule The Cop Universe In 2026

Mumbai, Focus News: 2026 is emerging as a landmark year for women-led crime and law enforcement narratives in Indian cinema, with a powerful lineup of actresses stepping into the police and investigative spaces. The growing demand for grounded crime thrillers and performance- centric storytelling is placing female cops at the center of mainstream entertainment, as actresses embrace roles built on conviction, realism, and authority.

Rani Mukherji In Mardaani 3: Among the names leading this wave is actress Rani Mukherji with Mardaani 3, continuing her long-standing portrayal of Senior Inspector Shivani Shivaji Roy — a franchise widely credited for opening mainstream space for women in uniform narratives. Mukerji's presence remains a benchmark reference within the genre. Joining her in the genre's evolving space are established and emerging names commanding strong audience attention.

Sheena Chohan In Jhatasya Maranam Dhruvam: Sheena Chohan, who makes her entry into the cop universe with a striking new police avatar for her upcoming Pan-Indian film Jhatasya Maranam Dhruvam. Sheena, acclaimed for her theatre foundation and work across both Indian and international projects, brings a credible, no-frills interpretation to the uniform, signaling her gravitation toward strong, structured characters. Her look and narrative positioning align with the industry's current emphasis on authenticity and restraint rather than stylized theatrics, marking her a pan India talent to watch in the expanding female cop landscape of 2026.

Sobhita Dhulipala In Cheekatilo: Sobhita Dhulipala steps into the investigative format with the Telugu crime thriller Cheekatilo, a project rooted in layered policing and psychological crime world-building. Known for her understated intensity, Dhulipala's move reinforces the rise of cerebral investigative dramas across industries.

Huma Qureshi In Bayaan: Huma Qureshi leads Bayaan, a procedural crime narrative driven by a female investigator navigating high-stakes policing environments. Qureshi's grounded screen authority and performance credibility make her a natural fit for the emerging law-enforcement format.

With these projects collectively in motion, 2026 is set to be dominated by women in uniform as the female cop universe gains prominence across multiple languages and platforms. As Sheena Chohan enters the space alongside leading names, the coming year signals a stronger, more visible presence for women-led law-enforcement storytelling in mainstream cinema.

Kalyan Jewellers to Grandly Unveil Flagship South Extension Showroom on 17 January

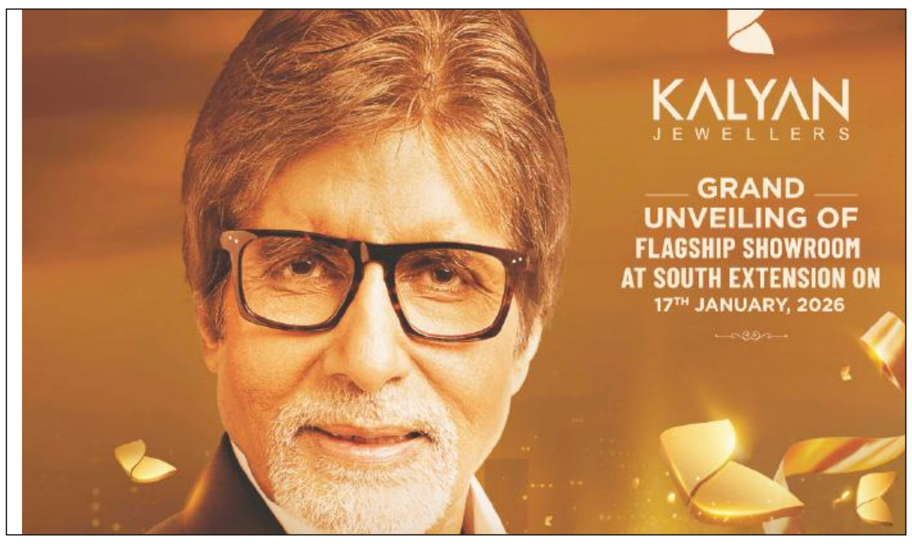

New Delhi, Focus News: Kalyan Jewellers, one of India's most trusted and leading jewellery brands, will grandly unveil its flagship showroom at South Extension on 17 January 2026. The re-launch marks a significant milestone for the brand, introducing a redesigned space that reflects elegance, innovation, and world-class retail standards. The flagship South Extension showroom has been thoughtfully reimagined with contemporary interiors, enhanced layouts, and sophisticated display zones. The upgraded store will showcase an extensive collection of gold, diamond, precious stone, and bridal jewellery, catering to evolving customer preferences while celebrating timeless craftsmanship.

Designed to deliver an immersive and premium shopping experience, the showroom combines modern aesthetics with customer-centric features such as improved lighting, spacious browsing areas, and personalized service zones. The re-launch reinforces Kalyan Jewellers' commitment to blending tradition with modern luxury.

True to its core values, Kalyan Jewellers will continue to uphold its promise of transparency and trust by offering BIS hallmarked gold, certified diamonds, and clear pricing policies at the South Extension flagship showroom. The grand unveiling on 17 January 2026 further strengthens Kalyan Jewellers' presence in the capital and underlines the brand's dedication to excellence, craftsmanship, and customer confidence.

NPS Vatsalya Scheme revamped: New rules aim to strengthen long-term financial protection for children

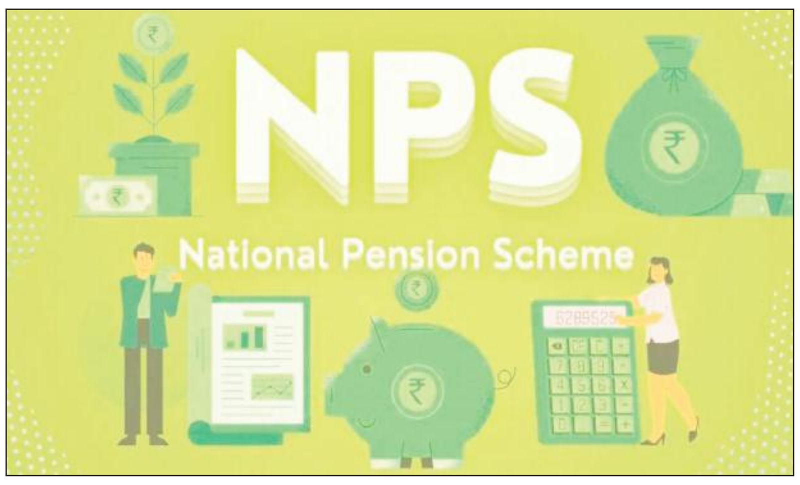

New Delhi: In a fresh development related to the NPS Vatsalya scheme launched for children, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has issued new and important guidelines. These changes are aimed at making the scheme more flexible, transparent, and beneficial for families, providing investors with relief when needed, and ensuring better long-term returns. For those unaware, the government rolled out the NPS Vatsalya in the 2024-25 budget, which is a pension scheme specifically designed for minor children.

The scheme gives the option to parents or guardians to invest in this scheme in their child's name to provide them with financial security and pension benefits in the future. Under the scheme officially launched on September 18, 2024, investments are continued until the child reaches 18 years of age. Later, these children have the option to continue the account or choose other alternatives.

Up to 75 per cent of the amount can be allocated to equities: According to the new rules, up to 75 per cent of the amount invested in NPS Vatsalya can be allocated to equities (the stock market). This step will enhance the chances of better potential returns. While traditional pension schemes have been known for the problem of low returns, the increased investment in equities will help build a strong fund for the child's future.

Once five years of the investment cycle are completed, guardians get the option to make partial withdrawals for needs, including the child's education, serious illness, or medical treatment.

Withdrawal of up to 25% of the accumulated contribution : The new rules allow for a withdrawal of up to 25 per cent of the total accumulated contribution in three instalments. This makes the scheme helpful not only for retirement but also for meeting temporary needs.

As the child turns 18, he/she will have options such as continuing the account for three more years, transferring it to a regular NPS account, or withdrawing the amount. Once the scheme matures, up to 80 per cent of the accumulated corpus can be withdrawn as a lump sum, while the remaining 20 per cent must be used to purchase an annuity. However, if the total accumulated amount is less than Rs 8 lakh, the entire corpus can be withdrawn in one go.

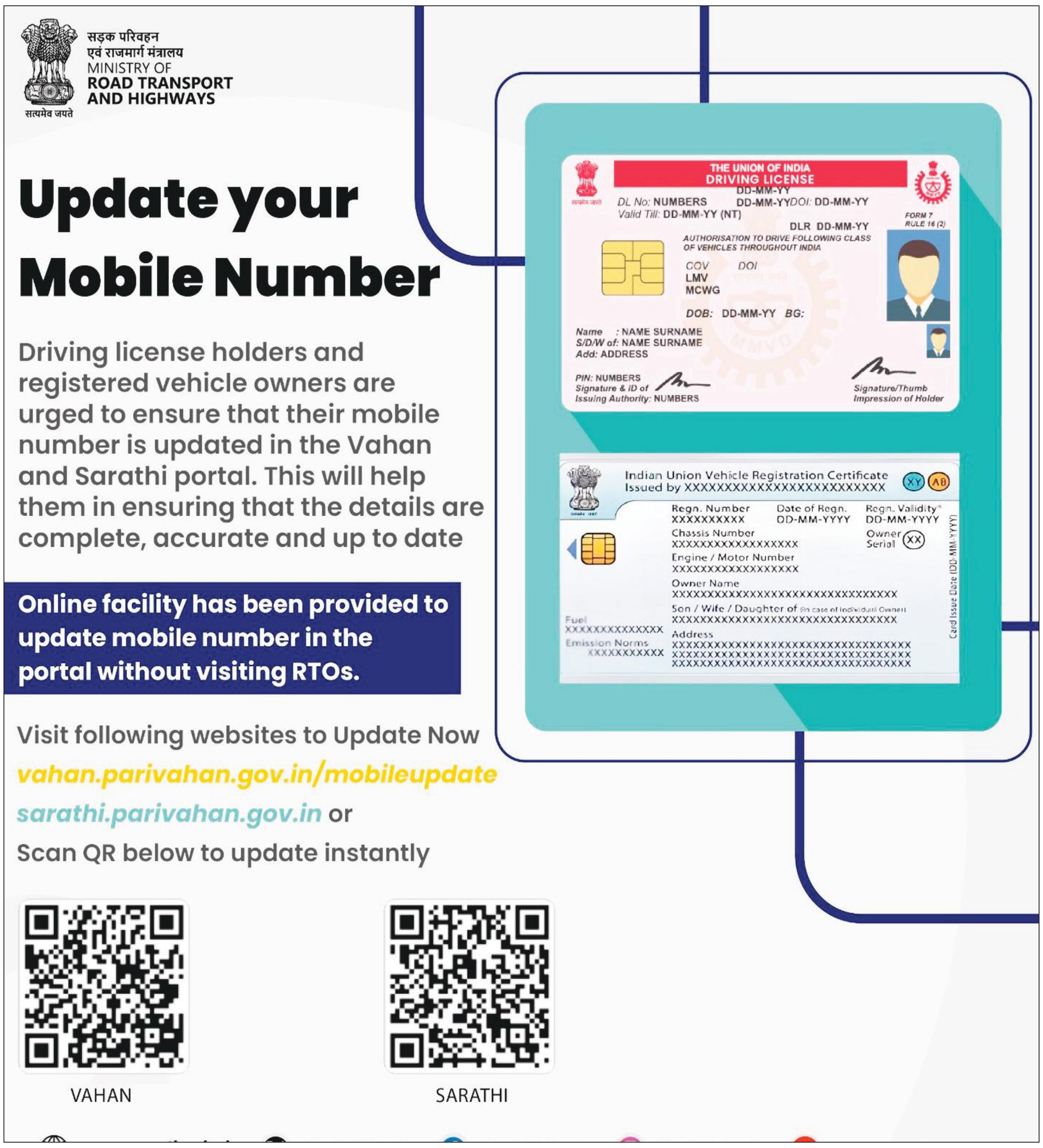

राजस्थान सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही: भजनलाल शर्मा

जयपुर, फोकस न्यूज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए राज्य सरकार अपनी नीतियों व निर्णयों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार ने पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों तथा छह लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं।'' उन्होंने कहा, ''पिछले दो वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारी सरकार हर वर्ष भर्ती कैलेंडर जारी कर रही है। इस वर्ष भी एक लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है। करीब दो लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई गई है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में चार लाख से अधिक युवाओं को 1,150 करोड़ रुपये का भत्ता दिया गया है।'' शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए नवीन युवा नीति भी जारी की गई है, जिससे उन्हें उद्यमशीलता, स्टार्टअप्स और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास भी हो रहा है।

राजस्थान विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया

'राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स 17 जनवरी को आएंगे जयपुर'

जी एन भट्ट

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। राजस्थान विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को नई दिल्ली में संसद के ऐतिहासिक संविधान भवन में राष्ट्रमंडल देशों के 28 वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला और केन्द्रीय मन्त्रियों जे पी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी के साथ ही प्रदेश के सांसदों, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाध्यक्षों, संसद सदस्यों और अन्य कई नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आईपीयू की प्रेसीडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण, राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिए गए प्रभावशाली भाषण को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और जनभागीदारी की मजबूती पर जोर देते हुए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग, श्रेष्ठ संसदीय प्रथाओं के आदान–प्रदान और क्षमता निर्माण के साथ ही साझा चुनौतियों का मिल कर समाधान करने का आह्वान किया है।

'राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष 17 जनवरी को जयपुर आयेंगे' : विधानसभाध्यक्ष ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन के बाद स्पीकर्स का 17 जनवरी को जयपुर भ्रमण का कार्यक्रम है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों के सम्मान में जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में 17 जनवरी को सायं राज्य विधानसभा द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजन रखा गया है।

अगले सात वर्षों में देश के बिजली क्षेत्र में 500 अरब डॉलर के निवेश की संभावना: सचिव पंकज अग्रवाल

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, भारत में अगले सात साल के दौरान उत्पादन, पारेषण और भंडारण सहित बिजली क्षेत्र में कुल 500 अरब डॉलर (लगभग 45 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की संभावना है। केंद्रीय बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने यह जानकारी दी। 'भारत इलेक्ट्रिसिटी' शिखर सम्मेलन 2026' के संबंध में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए अग्रवाल ने कहा कि देश में बिजली पारेषण नेटवर्क जल्द ही पांच लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो वर्तमान में 4.97 लाख सीकेएम तक पहुंच चुका है। उन्होंने भारत को एक उच्च विकास वाला बाजार बताते हुए कहा कि अगले सात वर्षों में बिजली उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा भंडारण और वितरण में निवेश की काफी क्षमता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बिजली क्षेत्र की वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलन 'भारत इलेक्ट्रिसिटी' शिखर सम्मेलन 2026' का आयोजन 19 से 22 मार्च तक नयी दिल्ली के यशोभूमि में किया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की और शिखर सम्मेलन से संबंधित ब्रोशर और टीजर फिल्म भी जारी की। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने कहा कि भारत को अब बिजली क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने 2024 में 250 गीगावाट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही 'बिजली संशोधन विधेयक 2026' पेश करने वाली है।

ईयू के शीर्ष नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे; मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना

नयी दिल्ली, (भाषा) यूरोपीय संघ (ईयू) की शीर्ष नेता उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका की व्यापार और टैरिफ (शुल्क) नीतियों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच, दोनों पक्ष 27 जनवरी को बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। वैश्विक व्यवस्था के अस्थिर प्रतीत होने के बीच, 25 जनवरी से कोस्टा और वॉन डेर लेयेन की नयी दिल्ली की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान ईयू और भारत द्वारा एक व्यापक वैश्विक एजेंडा तैयार करने पर विचार किए जाने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वित्त वर्ष 2023–24 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से व्यापारिक संबंधों के काफी मजबूत होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा करेंगे और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, वे 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह–अध्यक्षता भी करेंगे। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में विश्व के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। यूरोपीय संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ–भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना तथा प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ करना है। इसमें कहा गया है कि व्यापार, सुरक्षा और रक्षा, स्वच्छ परिवर्तन और जन सहयोग जैसे मुद्दे चर्चा के शीर्ष एजेंडे में शामिल रहेंगे। कोस्टा ने कहा, ''भारत यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। हम मिलकर नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। यह बैठक हमारी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे सहयोग में प्रगति लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।'' शीर्ष सूत्रों के अनुसार, शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब दुनिया वाशिंगटन की टैरिफ नीति के मद्देनजर व्यापार में व्यवधान का सामना कर रही है, प्रस्तावित समझौते से कई क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने में गुणात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के अलावा, दोनों पक्ष शिखर सम्मेलन में रक्षा समझौता और रणनीतिक एजेंडा तय कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। पंद्रहवां भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''विशेष रूप से फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के आयुक्तों की ऐतिहासिक भारत यात्रा के बाद, द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में विस्तारित और प्रगाढ़ हुए हैं।'' शिखर सम्मेलन में अपनाई जाने वाली नयी रणनीतिक कार्ययोजना में साझा हितों के पांच क्षेत्रों की पहचान की गई है।